कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल

संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QSDl : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी के नई दिल्ली स्थित निवास पर आयोजित राजग की बैठक में भाग लेते वरिष्ठ नेतागण।

संसद में बहस

राष्ट्रपति अभिभाषण

राजनाथ सिंह.......... 7

वेंकैया नायडू.......... 9

श्रमिक वर्ग के बीच व्यापक असंतोष

डॉ. मुरली मनोहर जोशी.......... 12

रेल बजट 2012&13

रेल बजट की मुख्य बातें.......... 14

आम आदमी हुआ बेहाल.......... 15

आम बजट 2012&13

आम बजट की मुख्य बातें.......... 22

लेख

राजनीति किसलिए?

&çHkkr >k.......... 17

रेल बजट : वायदे ज्यादा, काम कम

&ih;w"k xks;y.......... 20

चुनौतियों का सतही जवाब

&;'koar flUgk.......... 25

चुनौतियों से मुंह मोड़ता बजट

&,u d s flag.......... 27

महंगाई बढ़ाने वाला बजट

&ykM e/kukFk n s'kbZ.......... 29

अन्य

परिकर बने तीसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री.......... 6

बादल ने ली पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ.......... 13

बोध कथा

जनक का जवाब

मिथिला के राजा जनक से उनके एक मंत्री ने पूछा, 'महाराज, आप तो देहधारी हैं, फिर आपको विदेह अर्थात् बिना शरीर के क्यों कहा जाता है? 'राजा जनक बोले, 'मैं तुम्हें इसका जवाब कुछ दिनों में दूंगा।'

कुछ दिनों बाद उन्होंने घोषणा करवा दी कि हमारे मंत्री से भयंकर अपराध हो गया है, जिस कारण उन्हें एक सप्ताह बाद मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर उन्होंने उस मंत्री को बुलाया। मंत्री भय से कांपता उनके पास पहुंचा। जनक ने उसके आगे प्रेम से छत्तीस प्रकार के व्यंजन रखे और खाने को कहा। मंत्री भूखा होने पर भी मन से भोजन नहीं कर पाया, न ही उसे स्वाद का पता चला।

भोजन के बाद जनक ने कहा, 'तुमने यह नहीं बताया कि भोजन कैसा बना था, किसी में कुछ कमी तो नहीं थी?' मंत्री रोते हुए बोला, 'महाराज, एक सप्ताह बाद तो मेरी मौत होने वाली है। मुझे मौत के सिवाय कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैंने तो यह भी ध्यान नहीं दिया कि भोजन में क्या–क्या था?'

जनक बोले, 'यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। जिस तरह एक सप्ताह बाद आने वाली मौत के भय से तुम खाना खाते समय देह होते हुए भी विदेही हो गए थे। उसी तरह मैं हर समय अपने सामने मौत को देखता हूं। हर वक्त मौत को दिमाग में रखते हुए सभी कुछ उपभोग करते हुए भी उनसे अलग रहता हूं। मेरे अंदर उन वस्तुओं का मोह नहीं जागता। इसलिए सब मुझे विदेह कहते हैं। तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तुम्हें जवाब देने के लिए मैंने यह नाटक रचा था।'

संकलनः रेनू सैनी

साभारः नवभारत टाईम्स

व्यंग्य चित्र

नव संवत्सर 2069

शुभकामना संदेश

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुढी पड़वा, युगादी, चेटी चंड और नवरात्र के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों तथा दुनियाभर में रह रहे भारतवंशियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में श्री गडकरी ने कहा कि नव संवत्सर 2069 सभी के जीवन में खुशियां, प्रगति और समृद्धि लेकर आये।

कमल संन्देश की ओर से सुधी पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं।

यह कुर्सीबंधन है गठबंधन नहीं

समाधकीय

सरकार से पूछिए! क्या सरकार है? सरकार खुद कहेगी, कहीं दिख नहीं रही। जिस सरकार का सरकार से सरोकार न हो उस सरकार का सरकार में बने रहना कितना वाजिब है? सारा देश यही मानकर चल रहा है कि केन्द्र में सरकार बैठी है पर चल नहीं रही। फिर जो सरकार चल नहीं रही उसे चलाते रहना प्रत्यक्ष रूप से जनतंत्र का जनाजा ही निकालना कहा जाएगा। गत 65 वर्षों में लोकतंत्र कभी इतना लहुलुहान नहीं हुआ। भारत ने कभी लोकतंत्र को रोते नहीं देखा। आज भारत में लोकतंत्र सिसकियां ले रहा है। देश की चिंता किसी को नहीं। जैसे–तैसे बनी रहे सरकार और घिसटती सरकार को देखने के आदी होते जा रहे हम लोग शायद भगवान भरोसे ही लोकतंत्र को छोड़ना चाहते हैं। जब स्वयं का भरोसा नहीं होता तब उस काम को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। आज यही हालत भारत में लोकतंत्र की हो गई है। इससे हास्यास्पद स्थिति और क्या होगी कि सदन के भीतर प्रस्तुत हो रहा रेल बजट शाम होते–होते बजट प्रस्तुत करने वाले रेलमंत्री की राजनीतिक बलि ले लेता है। अब तक सुना था कि प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिमंडल में किसी को शामिल करते हैं और किसी को हटाते हैं। प्रधानमंत्री की मंशा से ही यह काम होता है पर तत्कालीन रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी के साथ जो कुछ घटा वह इस बात को उजागर करता है कि वर्तमान कांग्रेसनीत यूपीए सरकार का न कोई वजूद है, न कोई साख है और न कोई धाक है। कमजोर पायों की कुर्सी पर कोई मजबूत आदमी भी बैठे तो वह कमजोर हो जाता है। फिर डॉ. मनमोहन सिंह तो अपनी जिंदगी की तीन चौथाई जिंदगी तो नौकरशाही में गुजार दी, ऐसे मजबूरी के प्रधानमंत्री कमजोर पाए की कुर्सी पर कितने मजबूर हो गए हैं, ''रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे ने इस बात को जगजाहिर कर दिया है।''

यह गठबंधन की सरकार नहीं यह कुर्सी–बंधन की सरकार है। यह नैतिकता की नहीं अनैतिकता की सरकार है। किसी सरकार का अनैतिक हो जाना और कुर्सी के बंधन से बंध जाना अकर्मण्यता की पराकाष्ठा है। सरकार रूपी शरीर आत्माहीन हो चुका है। जब शरीर में अनेक आत्माओं का प्रवेश होता है तो उसका संबंध परमात्माओं से कम, भूतात्माओं से अधिक हो जाता है। अनास्था, अस्थिरता, असहाय, निरीहता, संकीर्णता, जीर्णता अपूर्णता, अशुभता, निर्दयता, क्रूरता जैसे अनेक विशेषणों से जुड़ी घटनाएं नित्य घटने लगती है। कुर्सी के मोह ने कांग्रेसनीत यूपीए सरकार को इतना मोह लिया है कि वह जनतंत्र के प्रत्येक आखर को भूल गई है। न नियम बचा है, न संविधान, न नीयत बची है और न कानून, न विवेक बचा है बल्कि आंतरिक संग्राम का अंतिम दौर चल रहा है। पासा किस ओर पलटेगा यह तो नहीं कहा जा सकता, पर कुर्सी के चारों पहिए, जिस पर कांग्रेसनीत यूपीए सरकार टिकी है, जरूर टूटेगी और केन्द्र की सरकार चारों खाने चित्त गिर पड़ेगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देश के घुटने तोड़कर अपने कुर्सी के पाए बचाना, यह न न्यायसंगत है और न नीतिसंगत। ऐसे माहौल में लोकतंत्र के हर उस सिपाही को, जो भारतीय होने का दावा करते हैं, दल से ऊपर उठकर एकसाथ आना होगा। देश बचेगा तो दल बचेगा। भारत बचेगा तो हम भारतीय रह पाएंगे। बीता समय लौटकर नहीं आता। बीता कल कहानी हो जाता है। आनेवाला कल योजना हो जाती है और वर्तमान अस्थिर हो जाता है। आज कांग्रेसनीत यूपीए सरकार का वर्तमान अस्थिरता के भयावह दौर से गुजर रहा है। कोई माई–बाप नहीं। जमीन पर कांग्रेस सपा–बसपा से लड़ती है और सदन में मोहब्बत का जाम टकराती है। अपराधी वे भी होंगे जो अपराध करने वालों को बचाने में थोड़ी या अधिक भूमिका निभाते हैं। जो सरकार नित्य भारत माता को कमजोर करती है उस सरकार को पनाह देना गुनाह की श्रेणी में ही आएगा।

कितनी विडंबना है कि सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ती है और सदन में तीनों ही गलबहियां करते हैं। राजनीति की यह नई धारा किसी सागर की ओर जाने की बजाय हमें किसी नाले या गटर में ले जाएगी। देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति उस मोड़ पर आकर खड़ी है जहां चारों ओर सिगनल के लाल ही लाल रंग दिख रहे हैं। जनता बाट जोह रही है कि कोई आगे आए। सिगनल के लाल रंग को हटाए। हरा रंग दिखाए जिससे चौराहे पर खड़ी भारत की राजनीति आगे बढ़ सके और सिसकते लोकतंत्र की सिसकियों को थाम सके।

समय बीतते देर नहीं लगती, 65 वर्ष कैसे गुजर गए पता नहीं लगा, पर यदि हमने समय को अब भी नहीं पहचाना और उसकी गति को न जाना तो शायद हम गुमनामी के उस दौर में चले जाएंगे जहां से निकलना दूभर सा हो जाएगा। अतः संभलने का वक्त है। हमें संभलने की दिशा में और लोकतंत्र को संवारने की दिशा में या तो संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा या समन्वय का। अब देखना यह है कि समन्वय और संघर्ष की भूमिका अपने पुरूषार्थ से कौन हासिल करता है? अवसर कांग्रेस को तो नहीं मिलेगा। आसार तो भाजपा के ही हैं पर भाजपा को बाजार से बचना होगा और विचार के प्रति समर्पित होना होगा। ■

पर्रिकर बने तीसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री

गत 9 मार्च 2012 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मनोहर पर्रिकर ने तीसरी बार गोवा के मुख्यरमंत्री पद को सुशोभित किया। राज्यपाल श्री के. शंकरनारायणन ने श्री पार्रिकर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ पांच अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले पांच मंत्रियों में चार भाजपा से, जबकि एक गठबंधन में सहयोगी एमजीपी से हैं। भाजपा से दयानंद मांडरेकर, लक्ष्मीकांत पारसेकर, मातन्ही सल्दाना और फ्रांसिस डिसूजा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। एमजीपी से रामकृष्ण धावलीकर मंत्री बने हैं।

गोवा के इतिहास में पहली बार शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के बजाय खुले मैदान में आयोजित किया गया।

गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में पहली बार भाजपा खुद बहुमत में आई है। उसके 21 विधायक हैं। तीन विधायक एमजीपी के और दो निर्दलियों का भी समर्थन मिल जाने से गठबंधन सरकार के पास 26 विधायकों का समर्थन है। 56 वर्षीय पारिकर इससे पहले दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन वह दोनों ही बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे।

पहली बार पार्रिकर ने अक्तूबर 2000 से 2002 तक सरकार चलाई थी। इसके बाद फरवरी 2002 में फिर उनकी सरकार बनी, जो 2005 तक चली। लेकिन गठबंधन में सहयोगी दलों के झटका देने के चलते उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। आईआईटी एजुकेटेड पारिकर को लोग उनकी सादगी और साफ छवि के लिए भी जानते हैं। उन्हें विकास की पहल करने और लोगों के बीच घुलने मिलने के लिए जाना जाता है। इन चुनावों में पार्रिकर ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अवैध खनन का मुद्दा जोरशोर से उठाया था। राज्य में कांग्रेस विरोधी लहर बनाने में इस मुद्दे की अहम भूमिका रही।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राष्ट्री य महामंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता सर्वश्री प्रकाश जावड़ेकर, राजीव प्रताप रूड़ी, शहनवाज हुसैन, लोकसभा में पार्टी के उपनेता श्रीगोपीनाथ मुंडे, कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री सदानंद गौड़ा और भाजपा गोवा प्रदेश प्रभारी सुश्री आरती मेहरा उपस्थित थे। ■

यूपीए की विश्वसनीयता खत्म : राजनाथ सिंह

गत 12 मार्च 2012 को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने बजट–सत्र में संसद के दोनों समवेत सदनों को संबोफ्रित करते हुए अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। श्रीमती पाटिल ने अपने भाषण में यूपीए सरकार की उपलब्फ्रियों का जिट्र किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर फ्रान्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसदों ने उपलब्फ्रियों की पोल खोलते हुए जमकर प्रहार किया।

लोकसभा में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अफ्रयक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पांच राज्यों के विफ्रानसभा चुनावों के परिणामों से यह साबित हो गया है कि केन्द्र सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। वहीं राज्यसभा में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अफ्रयक्ष श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यूपीए गठबंफ्रान में शामिल दल जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उससे साफ झलकता है कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने में नाकाम रही है। हम यहां श्री राजनाथ सिंह एवं श्री वेंकैया नायडू द्वारा दिए गए भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:–

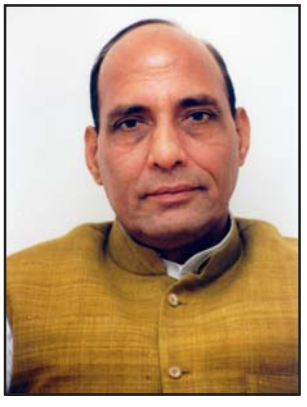

jk ष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें कुछ ऐसे सुझाव आएंगे जिनसे राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर आम सहमति बने और इससे सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में सुविधा रहती है। राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विपक्ष सरकार को सहयोग देना चाहता है किन्तु आज इस सरकार की मानसिकता यह बन गई है कि वह विपक्ष से रचनात्मक सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और हम लोगों ने भारत के संविधान में संघीय ढ़ांचा स्वीकार किया है। सरकार का प्रयास यह होना चाहिए कि केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग बना रहे लेकिन आज स्थिति विपरीत दिखाई देती है। आज केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग के बजाए एक प्रतिस्पर्धात्मक तथा टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। हाल ही में इस सरकार ने एनसीटीसी के गठन का निर्णय किया है। देश के कई मुख्यमंत्रियों ने इसका यह कहकर विरोध किया कि सरकार ने राज्यों को विश्वास में लिए बिना यह कदम उठाया है। अब प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस बारे में निर्णय राज्यों से विचार–विमर्श के बाद लिया जाएगा फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में एनसीटीसी के गठन के उल्लेख का क्या औचित्य है। यह सरकार देश को आतंकवाद के संकट से मुक्ति दिलाने में गंभीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 2004 का चुनाव पोटा का मुद्दा बनाकर लड़ा था और सत्ता में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले एक सशक्त और प्रभावी आतंकवाद रोधी कानून पोटा को रद्द कर दिया था। देश के कई राज्यों ने आतंकवाद रोधी कानून बनाए किन्तु उन्हें भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है फिर यह कैसे माना जाए कि यह सरकार देश को आतंकवाद के संकट से मुक्ति दिलाने में गंभीर है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विपक्ष पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है किन्तु इसके लिए सरकार में दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए जिसका आज अभाव दिखाई देता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि 2011 में 18 स्लीपर मॉडयूल्स को नष्ट किया गया है किन्तु मीडिया की खबरों के अनुसार इस समय देश में 700–1000 तक स्लीपर मॉडयूल प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। एनसीटीसी के माध्यम से सरकार राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना चाहती है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल के मामले में सरकार उसे पुलिस की शक्तियां देना चाहती है जो कि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना सरकार सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा निवारण विधेयक लाई है। दूसरी ओर राज्य सरकारों ने अनेक विधेयक पारित किए हैं और उन्हें केन्द्र की मंजूरी के लिए भेजा है किन्तु वे सारे विधेयक वर्षों से केन्द्र की मंजूरी के लिए लंबित पड़े हुए हैं।

तेलंगाना का मुद्दा क्षेत्रीय आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में अलग तेलंगाना राज्य के

गठन का कोई उल्लेख नहीं है। तेलंगाना राज्य के गठन में भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग करेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी गंभीर समस्यायें पैदा हो रही हैं। वहां पर भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है कि वहां पर लोगों की सड़क, पानी और बिजली की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। उन्हें केवल विशेष पैकेज देने से इन समस्याओं का हल नहीं होगा अपितु इसके लिए सरकार को विशेष प्रयास करने होंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में लैप्सेबल कंट्रोल पूल को नॉन लैप्सेबल कंट्रोल पूल के रूप में मान्यता दी गई है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में चीन की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। चीन हमारे रक्षा मंत्री के अरुणाचल दौरे पर भी विरोध करता है। मेरा मानना है कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से विरोध दर्ज नहीं कराया और प्रभावी कूटनयिक प्रयास नहीं किए। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। इस संबंध में भारत सरकार को चीन और भारत की संयुक्त निरीक्षण समिति के गठन का प्रयास करना चाहिए और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चीन, बंगलादेश और भारत तीन को मिलकर एक त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय जल संधि करनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों की बात की गई किन्तु सामरिक दृष्टि से जो खतरा पैदा हो रहा है उसका अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई।

राष्टपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि 2011 में 18 स्लीपर मॉडयूल्स को नष्ट किया गया है किन्तु मीडिया की खबरों के अनुसार इस समय देश में 700–1000 तक स्लीपर मॉडयूल प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। एनसीटीसी के माफ्रयम से सरकार राज्यों के अफ्रिकारों में हस्तक्षेप करना चाहती है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल के मामले में सरकार उसे पुलिस की शक्तियां देना चाहती है जो कि राज्य सरकारों के अफ्रिकार क्षेत्र में आता है।

मीडिया में प्राप्त खबरों के अनुसार अपने वित्तीय घाटे को देखते हुए सरकार रक्षा बजट में कुछ कमी करने जा रही है। रक्षा बजट में कटौती नहीं की जानी चाहिए बल्कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री से संसद को आश्वस्त किया था कि किसी भी सूरत में वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.6 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ेगा किंतु हाल ही में जारी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होते–होते वित्तीय घाटा 5.6 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। आर्थिक विशेषज्ञ भी यह मानने लगे हैं कि वित्तीय घाटा बेकाबू होता जा रहा है तथा इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार और घोटाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार वर्ष 2012–13 की पहली तिमाही में वृद्धि दर 6 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण मे कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष 8 प्रतिशत से अधिक रहेगी। बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है केवल मनरेगा से बेरोजगारी की चुनौती का सामना नहीं किया जा सकता है इसके लिए सरकार को प्रभावी नीति बनानी होगी। राजग के शासन काल में वृद्धि दर बढ़ी किंतु मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में रही। संप्रग सरकार के दौरान महंगाई निरन्तर बढ़ रही है अर्थात् लोगों को महंगाई से कोई राहत नहीं मिलेगी। मनरेगा में कुछ लोगों को रोजगार मिला है किन्तु इसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है।

दिसम्बर 2011 तक इस योजना पर एक लाख चार सौ बावन करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसमें सरकार वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का दावा करती है किन्तु इस वित्त वर्ष में दिसम्बर तक प्रति परिवार केवल 32 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा मे व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किए जाने की आवश्यकता है। आज भी गांव से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। किसानों की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। आंध्र प्रदेश मे किसान क्राप होली डे जैसे निर्णय लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने जा रही है किन्तु यदि उत्पादन नहीं बढ़ा तो इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2011–12 में किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए जाएंगे। इसके पहले 4 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का डिसबर्समेंट किसानों को हुआ था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंडीगढ़ और दिल्ली में जहां एग्रीकल्चर लैण्ड का एक्वीजिशन बहुत हुआ है, वहां पर 32 हजार 400 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़.इन राज्यों को मिलाकर केवल 31 हजार करोड़ रुपये का कर्ज वितरित हुआ है। कैसे किसान उत्पादन बढ़ाएंगे? मैं समझता हूं कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। पिछले वर्ष यह बताया गया था कि 241.56 मिलियन टन उत्पादन हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि इतने उत्पादन

से इस देश का कल्याण नहीं होगा, उत्पादन को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए संसद का 7 या 10 दिनों का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए जिससे कृषि नीति में क्या–क्या चेलेंज लाए जा सकते हैं, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार हो सके। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मैं देख रहा था कि जो समय से कर्ज की अदायगी कर देंगे, उनकों 3 फीसदी की छूट दी जाएगी, यदि उनको चार प्रतिशत रेट ऑफ इंट्रेस्ट देना पड़ेगा। मैं भी फार्मर्स कम्युनिटी से आता हूं, मैं कहना चाहूंगा सरकार को दृढ इच्छाशक्ति के साथ यह फैसला करना चाहिए कि किसानों को एक प्रतिशत रेट ऑफ इंट्रेस्ट पर एक साल के लिए लोन मुहैया कराया जाए। यदि वह एक साल तक कर्ज की अदायगी नहीं करता, तो उसके बाद उसे बढ़ाकर उन से तीन प्रतिशत रेट ऑफ इंट्रेस्ट लीजिए, लेकिन तीन प्रतिशत से ज्यादा रेट ऑफ इंट्रेस्ट एग्रीकल्चर लोन पर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। सवाल यह उठता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा देवास–एंट्रीक्स डील के संबंध नियमों को तोड़ कर देवास को क्यों समय–समय पर मंजूरी दी जाती रही है, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है। अभिभाषण के प्रारम्भ में ही चौथे पैराग्राफ में करप्शन और ब्लैकमनी की चर्चा की गई है। मैं समझता हूं कि लोकपाल बिल पारित कर देने से ही करप्शन को हम मिनीमाइज़ कर देंगे, ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्टिव मैकेनिज्म की आवश्यकता होगी। उस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिए। यह सारा सिलसिला चल ही रहा था कि केवल चुनावी सफलता हासिल करने के लिए मजहब के आधार पर आरक्षण देने की घोषणा कर दी गई। लेकिन जब हमने देखा कि भारत के संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है और स्वयं पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने भी 1961 में यह कहा था कि साम्प्रादायिक आधार पर आरक्षण भारत के लिए एक छोटी सी गलती नहीं होगी, बल्कि भारत के लिए विनाशकारी होगा, भारत के लिए विभाजनकारी होगा। उन्हीं की विरासत की राजनीति करने वाले लोग आज उनकी मंशा के विपरीत जाकर मजहब के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। इसलिए धर्म और मजहब के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, आजाद भारत का पुनर्विभाजन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

इस समय सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, प्रतिपक्ष में होते हुए भी हम लोग इस संकट से देश को उबारने के लिए सरकार को सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सरकार की विश्वसनीयता, सरकार का इकबाल इस समय देश में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैं समझता हूं कि उसे रेस्टोर करने की जरूरत है, यदि सरकार उसे रेस्टोर नहीं कर सकती है, तो मैं समझता हूं कि सरकार के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इतना ही निवेदन करते हुए यह जो धन्यवाद प्रस्ताव है इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

राज्यसभा

घटक दलों में संवादहीनता के चलते यूपीए डांवाडोल : एम. वैंकैया नायडू

माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश में पूछे जा रहे एक महत्वपूर्ण प्रश्न की अनदेखी की गई है। पिछले दिनों के घटनाक्रम से यह प्रतीत होता है कि सरकार सभी मोर्चों पर असफल रही है। इस सरकार में उत्तराखण्ड से एक मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है। रेलमंत्री ने रेल बजट प्रस्तुत करने के बाद कथित रूप से त्यागपत्र दे दिया है सरकार ने अपने घटक दल के एक सदस्य को अपनी तरफ मोड़कर गठबंधन के धर्म को तोड़ा है। इन सबसे लगता है कि सरकार की नींव की ईंटे एक–एक कर खिसक रही हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक फीका भाषण है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई दृष्टिकोण नहीं है। सरकार के अपने घटक ही सभा में बाधा डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि सरकार देश के समक्ष आने वाली चुनौतियों और मुद्दों के संबंध में स्वतंत्र और स्पष्ट चर्चा नहीं कर पा रही है तथा कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले वह अपने घटक दलों के साथ सर्वसम्मति नहीं बना पाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 4 में कहा गया है, 'मेरी सरकार एक ईमानदार और ज्यादा सक्षम सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध रही है'। परंतु देश में लाखों करोड़ रूपये के कई घोटाले हुए हैं।

काले धन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने वचन दिया था कि सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर एक रोडमैप बनाएंगे। परंतु इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। सरकार ने घोटालों में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कुछ नहीं किया। केवल न्यायालयों ने ही उन्हें जेल भेजा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक नया विधेयक लाने की बात कही गई है। सरकार ने देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में श्रीलंका के तमिलों की दशा के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पड़ोसी होने के नाते हमारा श्रीलंका और श्रीलंका के तमिलों के साथ विशेष रिश्ता है।

सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ाये परंतु अपने घटक दलों के दबाव में उन्हें वापस ले लिया। एनसीटीसी के संबंध में सरकार ने 2 मार्च की तारीख तय की परंतु विरोध के कारण इसके कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया। संघीय ढांचे में केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि वह किसी महत्वपूर्ण कानून पर राज्यों से परामर्श करे और उनके विचार जाने। सरकार पहले तो घोषणा करती है और उसके बाद विचार–विमर्श करती है। इसी प्रकार, कपास के निर्यात पर प्रतिबंध के मामले को देखें। सरकार ने 5 मार्च को कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और 12 मार्च को इसे उठा लिया। यह क्या तमाशा है? इस सरकार में एकता और स्पष्टता न होने के कारण ही यह सब कुछ हो रहा है। सरकार प्रभावी और प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य नहीं कर रही है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में संघीय ढांचे पर हमला एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। शक्तियों के विक्रेंदीकरण के बजाय केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति बनती जा रही है। गुजरात के संबंध में जीयूजेसीओसी विधेयक पर केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दिए जोन के मामले को चार साल से लटकाया हुआ है। एनसीटीसी निरंकुशता की तरफ उठाया गया एक कदम है और यह राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था के अधिकार का अतिक्रमण है। गृह सचिव पुलिस महानिदेशकों से कहते हैं कि मुख्यमंत्रियों के स्टेनो मत बनिए। यह अहंकार की हद है और सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। रेल सुरक्षा बल अधिनियम, लोक सेवा (संरक्षण और विनियमन विधेयक) 2010 और गुजरात में राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के मामलों में हस्तक्षेप के उदाहरण हैं।

प्रस्तावित विधेयक की धारा 20 राज्य की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह सरकारिया आयोग सहित विभिन्न आयोगों की सिफारिशों के भी खिलाफ है। इसे एक 'सांप्रदायिक विधेयक' कहूंगा। यह विधेयक सांप्रदायिकता की रोकथाम के लिए नहीं है। यदि यह विधेयक एक अधिनियम बन जाता है तो देश का और विभाजन करने की मांग होगी। यह लोगों को 'अल्पसंख्यक' और 'बहुसंख्यक' वर्गों में विभाजित करेगा। वास्तव में, यह एक कठोर विधेयक है। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद से लड़ाई एक साझा जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ना चाहिए। तीसरा बिंदु गैर–कांग्रेसी राज्यों के प्रति भेदभाव के बारे में है। सरकार पूरा श्रेय लेना चाहती है। इसके लिए इस सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरों को राष्ट्रीय राजमार्ग योजना से हटा दिया है। वह विभिन्न योजनाओं के नाम बदल रही है और अपने कांग्रेसी नेताओं के नाम का उपयोग कर रही है।

काले ध्रान के मुघे पर प्रध्राानमंत्री ने वचन दिया था कि सद्दाा में आने के 100 दिनों के भीतर एक रोडमैप बनाएंगे। परंतु इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। सरकार ने घोटालों में शामिल व्यक्तियों को गिरतार करने के लिए कुछ नहीं किया। केवल न्यायालयों ने ही उन्हें जेल भेजा है।

कोयला, ताप बिजली, खाद्यान्न, 'नरेगा' के धन, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि के आवंटनों के संबंध में गैर– कांग्रेसी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र 167 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश में 70 लाख टन कोयले की जरूरत है, लेकिन राज्य में केवल 11 लाख टन कोयला ही आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की हालत बहुत बुरी हैं। केन्द्र उन सड़कों को उनके मरम्मत कार्यों के लिए राज्य सरकार को नहीं सौंप रही है। मध्य प्रदेश में 37 लाख परिवार बेघर हैं। लेकिन, इंदिरा आवास योजना के तहत 70,000 घरों को ही आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। मध्य प्रदेश में 68 लाख 'बीपीएल' परिवार हैं, लेकिन केन्द्र ने केवल 41 लाख परिवारों को खाद्य सामग्री आवंटित की है। केन्द्रीय सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में रबी की फसल को बचाने के लिए एक रूपया भी अब तक जारी नहीं किया है। गुजरात की सीमा संवेदनशील है। केन्द्र, गुजरात को एक विधेयक अधिनिमित करने की अनुमति नहीं दे रहा है। कपास के मामले में, अब केन्द्र सरकार ने प्रतिबंध को वापस लेने की घोषणा की है लेकिन उसने कुछ शर्तों को लगा दिया

है। यही स्थिति कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों की है जो गैर–कांग्रेसी दलों द्वारा शासित दलों द्वारा शासित हैं। इससे भारत के संविधान का संघीय ढांचा कमजोर हो जायेगा।

कांग्रेस, 'सीबीआई' का उपयोग सत्ता में बने रहने के और विपक्ष को अस्थिर करने के लिए तथा सहयोगी दलों पर नियंत्रण रखने के लिए करना चाहती है। यह संगठन एक राजनीतिक औजार बन कर रह गया है। अधिकांश विपक्षी नेताओं को 'सीबीआई', आसूचना ब्यूरो, आयकर विभाग और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा परेशान किया जाता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग और चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा गया है। भारत सरकार को इन संवैधानिक और सांविधिक निकायों को मजबूत बनाना चाहिए। कीमतों में वृद्धि के संबंध में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल एक पंक्ति है कि 'मूल्य नियंत्रण में हैं'। लेकिन हर वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के तहत कीमतों पर नियंत्रण था और रूपए की स्थिति मजबूत थी। जब भी कोई समस्या उठती है तो सरकार अंतरराष्ट्रीय स्थिति को दोषी ठहराती है। आजादी के इतने सालों के बाद, हम आत्म–निर्भर नहीं हो पाए हैं। ब्याज दरों में 13 गुना वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम कीमतों, उर्वरक की कीमतों और 'ईएमआई' में वृद्धि हुई है। कीमतों में ऐसी वृद्धि से आम आदमी का बजट एक दुःस्वप्न में परिवर्तित हो गया है।

कीमतों में वृद्धि के संबंफ्रा में, राष्टौपति के अभिभाषण में केवल एक पंक्ति है कि 'मूल्य नियंत्रण में हैं'। लेकिन हर वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के तहत कीमतों पर नियंत्रण था और रूपए की स्थिति मजबूत थी।

इसके अलावा, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.6 प्रतिशत रखा गया था। पिछले तीन वर्षों में, प्रति वर्ष खर्च में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। व्यय पर नियंत्रण के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। विनिवेश के लक्ष्य के संबंध में उपलब्धि क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आ रही है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों निवेशक अपना विश्वास खो रहे हैं। लोग बाहर जाकर निवेश करना चाहते हैं। बुनियादी ढांचे के साथ क्या हो रहा है? देश में बिजली की आपूर्ति और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या किया जा रहा है? देश के विभिन्न भागों में विभिन्न बिजली परियोजनाओं की प्रगति क्या है? गैस, 'नरेगा', खाद्य और उर्वरक के मामले में सब्सिडी में कटौती की गई है। किसान आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा मात्र से नहीं जीवित रह सकते हैं। 'नरेगा' को कृषि के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि किसानों को भी मजदूरी मिल सके।

उत्तर–पश्चिम–दक्षिण–पूर्व कोरीडोर के संबंध में प्रगति बहुत ही निराशाजनक है। इसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2007 में पूरा किया जाना चाहिए था। तीन वर्षों से ज्यादा समय से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कोई अध्यक्ष नहीं है। नागर विमानन क्षेत्र में एक बड़ी मुसीबत है। मुम्बई, पुणे के जर्मन बेकरी और दिल्ली उच्च न्यायालय में विस्फोट मामलों का क्या हुआ? राजधानी में भी आतंकवाद अपना बदसूरत सिर उठा रहा है। महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ? राष्ट्रपति का अभिभाषण नदियों को जोड़ने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं करता है। इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। देश में गंगा, कावेरी और अन्य प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए उपाय शुरू किए जाने चाहिए।

देश में किसानों की आत्महत्या के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का क्या हुआ? यह एक ज्वलंत समस्या है। आज किसान संकट में हैं क्योंकि लागत बढ़ती जा रही हैं और कृषि मूल्य स्थिर हैं। कृषि क्षेत्र में उद्व्रजन हो रहा है। बयालीस प्रतिशत किसान अन्य व्यवसायों की ओर पलायन करना चाहते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक समस्या है। उनके विकास के लिए हैदराबाद–कर्नाटक के जिलों को विशेष दर्जा देने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करने के कर्नाटक के अनुरोध का क्या हुआ? एयर इंडिया के पुनर्वास के संबंध में मामला शोचनीय है। जब हम विमान पत्तन पर जाते हैं तो विमान पत्तन के कर्मचारियों का कहना है कि तीन महीनों से उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। गंगा को साफ करने से संबंधित मिशन का क्या हुआ? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठकों को समय से आयोजित नहीं किया गया है। वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी सरकार में से विश्वास खोते जा रहे हैं। सरकार ढुलमुल स्थिति में है। सरकार में अंदुरूनी अस्थिरता है क्योंकि वहां कोई वैचारिक सामंजस्य नहीं है। गठबंधन के कुछ सहयोगी विपक्ष की भूमिका में आना चाहते हैं। विपक्षी दल को दोषी ठहराया गया है कि वह सभा को कार्य करने नहीं दे रहा है। लेकिन, हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को रचनात्मक समर्थन दे रहे हैं। हमने सहकारी विधेयक पर समर्थन दया है। आपको अपने खुद के सहयोगियों में विश्वास नहीं है। आप उन लोगों के साथ विचारविमर्श नहीं करते हैं। ऐसी संवादहीनता क्यों है? ■

जब असंतुलन दूर होगा तब भारत महान होगा : डॉ. जोशी

गत 19 मार्च 2012 को लोकसभा में ''सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण श्रमिक वर्ग के बीच व्यापक असंतोष से उत्पन्न स्थिति के बारे में'' हुई चर्चा के दौरान भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी द्वारा दिए गए भाषण का सारांश :

गम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो किसी एक राजनीतिक पार्टी या किसी एक सरकार से संबंधित नहीं है। यह देश की 70 से 75 प्रतिशत गरीब जनता के भाग्य से संबंधित है जो किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। संविधान में कहा गया है कि वह राज्य सभी कामगारों के अच्छे जीवनस्तर के लिए प्रयास करेगा। संविधान में राज्य को कमजोर वर्गों के विशेषतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए और उन्हें सामाजिक अन्याय और हर प्रकार के शोषण से बचाने का भी निदेश दिया गया है।

नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर ने कहा है कि सबसे अधिक मजदूरों का शोषण एग्रीकल्चर वेज वर्कर के मामले में होता है। उनमें से पचास प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। 94 प्रतिशत मजदूर इस देश में असंगठित क्षेत्र में हैं, जिसमें से 11 करोड़ लोग कृषि मजदूर हैं। इतनी बड़ी मजदूर संख्या की आर्थिक स्थिति क्या है। सरकार की नीतियों ने अभी तक इसके बारे में क्या किया है? क्या इन मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है? यह बुनियादी सवाल है। नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर के अनुसार भारत में अधिकांश कृषि मजदूरों की वार्षिक आय इतनी कम है कि वे अपनी न्यूनतम उपभोग की आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण है कि उन्हें पर्याप्त मजदूरी तो अलग, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड किसे कहेंगे? क्या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ केवल धनी लोगों के लिए होगा या एक सामान्य आदमी को भी यह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा? वर्ष 1948 में बनाया गया मिनिमम वेज एक्ट क्या आज की परिस्थिति में ठीक है? अगर इस देश की आबादी का 60–70 प्रतिशत इस तरह से गुजारेगा तो आप इसको बड़ा क्या बनायेंगे? अगर 70–75 करोड़ लोग इस दुर्दशा से ग्रस्त हैं, आर्थिक दृष्टि से बदहाली में हैं जो बीमारी में इलाज नहीं करा सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, दो जून खाना नहीं खा सकते, ऐसे इस देश भारत को हम दुनिया की महान शक्ति बनाने का दावा कैसे कर सकते हैं? वह केवल कागजों में होगा। हमारे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। 15 से 29 वर्ष की आयु की वह शक्ति है जो सबसे प्रोडक्टिव है, सबसे ऊर्जावान है। अगर वह पिछड़ गयी तो फिर वह बहुत सालों तक पिछड़ी रहेगी।

भारत आगे वर्ष 2025–30 तक नहीं, शायद वर्ष 2040 तक दुनिया का सबसे नौजवान देश रहेगा। प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर, इन दोनों में एम्प्लॉयमेंट घट रही है। वह ईमानदार आदमी मेहनत से काम कर रहा है। उसे आप कांट्रैक्ट के लिए भेज रहे हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको आप प्रमोशन पर प्रमोशन दिए जा रहे हैं। सी.ई.ओ. की पगारें किस तरह बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ 15 रुपए प्रतिदिन के ऊपर आप लोगों को रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 25–26 रुपए होने पर और 32 रुपए होने पर तो वह अमीर हो जाता है। एक उद्योगपति की आमदनी 17 लाख रुपए प्रतिदिन है और उसी के यहां आप कोई न्यूनतम वेतन तय नहीं करना चाहते। बीड़ी मजदूरों और बुनकरों की संख्या हजारों–लाखों है। संविधान के अंतर्गत उन्हें जीवन का अधिकार मिला है। जो

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हैं, उनके प्रस्तावों की आप सम्पूष्टि नहीं करते। मैं एक बात के बारे में आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह जो आई॰एम॰एफ॰ और वर्ल्ड बैंक की नीतियां हैं वे दुनियाभर में फेल हो गई हैं। उन नीतियों का मतलब केवल ग्रोथ और ग्रोथ के लिए इनइक्वेलिटी कम्पलसरी है। वेस्टर्न सिस्टम ऑफ ग्रोथ के अनुसार बिना इनइक्वेलिटी के ग्रोथ नहीं हो सकती।

हमारे पड़ोस में चाइना है, वहां भी इनइक्वेलिटी है। वहां भी प्रोस्पैरिटी बढ़ रही है, मगर लैबरर्स में असंतोष वहां भी बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन की पॉलिटिक्स है, यह जो भी अर्थव्यवस्था है यह इनइक्वेलिटी पर बेस्ड है। लेबर मिनिस्ट्री के अनुसार एफडीआई नहीं आना चाहिए। अगर एफडीआई

इक्कीसवीं सदी अगर भारत की होनी है और भारत को यदि महान बनना है तो पहला संकल्प यहां से शुरू करना होगा कि भारत के हर व्यक्ति को मिनिमम वेजेज दिया जाएगा और सारे असंतुलन को दूर किया जाएगा।

यहां रीटेल में आएगी, सारे श्रमिकों की दुर्गति होगी और सारे उद्योगपतियों की दुर्गति होगी। जो अर्थव्यवस्था है यह बुरी तरह से फेल हो गई है। ये रिफार्म्स केवल बड़े आदमियों के रिफार्म्स हैं, यह गरीब आदमियों के नहीं हैं। वैश्वीकरण गरीबों के हित में नहीं हैं। पश्चिम लोग जॉब्स एंड जॉब्स एंड जॉब्स कह रहे हैं और वहां के जो नए आर्थिक विचारक हैं, वे चिंतित हैं। लोगों को उचित मात्रा में वेतन नहीं मिलेंगे, तो देशों में भीषण क्रांतियां हो सकती हैं। अगर हमारे देश में बेसहारा लोगों ने अगर यह ठान लिया कि इस सारी अर्थव्यवस्था को बदलना है, तो उस अस्सी करोड़ जनसंख्या के सामने आप कितने दिन टिकेंगे? आप ने नए बजट में चालीस हजार करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स दिया है वह इसी गरीब आदमी के ऊपर जा रहा है। पूरा मजदूर के ऊपर जा रहा है। जिनके लिए अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। केवल इसी भारत के लिए नहीं दुनिया के तीन बिलियन आदमियों की लड़ाई हमें अपने संसद के माध्यम से छेड़नी है कि कहीं भी कोई भूखा नहीं रहेगा। इक्कीसवीं सदी अगर भारत की होनी है और भारत को यदि महान बनना है तो पहला संकल्प यहां से शुरू करना होगा कि भारत के हर व्यक्ति को मिनिमम वेजेज दिया जाएगा और सारे असंतुलन को दूर किया जाएगा। ■

पंजाब

बादल ने ली पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ

शिरोमणि अकाली दल के नेता श्री प्रकाश सिंह बादल ने 14 मार्च 2012 को इतिहास रचते हुए पांचवीं बार पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह अकाली–भाजपा गठबंधन सरकार का लगातार दूसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं। राज्यपाल शिवराज वी पाटिल ने चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर चप्परचिड़ी में बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल में श्री प्रकाश सिंह बादल व उनके पुत्र श्री सुखबीर बादल को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई।

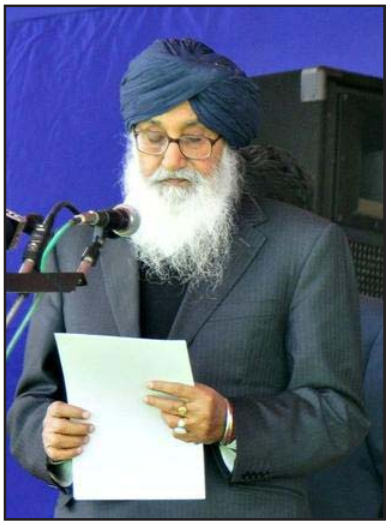

कैबिनेट रैंक के 16 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की जिनमें चार सहयोगी दल भाजपा से हैं। श्री प्रकाश सिंह बादल ने 1997 और 2007 से दो बार पांच साल का कार्यकाल पूरा किया है। इससे पहले वह 1977 से 1980 और 1970 से 1971 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शपथ ग्रहण के अवसर पर मौजूद नेताओं में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांता कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा, जनता दल (यू) के नेता शरद यादव, केंद्रीय मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल, इनेलो प्रमुख श्री ओमप्रकाश चौटाला, कर्नाटक के पथ परिवहन मंत्री श्री सीएम उडासी, एआईडीएमके सांसद श्री थंबी दुरै शामिल थे। अकाली–भाजपा गठबंधन ने 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 68 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था, जबकि विपक्षी कांग्रेस को सिर्फ 46 सीटें ही मिल पाई थीं। ■

रेल बजट 2012&13 की मुख्य बातें

रेल बजट 2012–13 को लेकर जमकर बवाल मचा। यूपीए सरकार की आंतरिक कमजोरी, घटक दलों के बीच संवादहीनता और अविश्वसनीयता को पूरे देश ने देखा। गौरतलब है कि केन्द्रीय रेल मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी ने 14 मार्च 2012 को रेल बजट श्स्तुत किया। उन्होंने रेल की सभी श्रेणियों में किराया बढ़ाने का श्स्ताव रेल बजट में पेश किया। सेकेंड क्लास में 2–3 पैसे श्ति किलोमीटर, स्लीपर में 5 पैसे श्ति किलोमीटर और एसी थ्री टियर में 10 पैसे श्ति किलोमीटर बढ़ोतरी का श्स्ताव पेश किया था। रेलमंत्री त्रिवेदी के इस श्स्ताव से उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की श्मुख सुश्री ममता बनर्जी आह्वोशित हो उठीं और अंततः दिनेश त्रिवेदी की रेल मंत्री की कुर्सी से छुट्टी हो गई। उनकी जगह मुकुल रॉय को नया रेल मंत्री बनाया गया। और जैसा कि अंदेशा था रॉय ने रेल बजट पर 22 मार्च 2012 को लोकसभा में जवाब देते हुए सेकेंड, स्लीपर और एसी थ्री टियर में किराया बढ़ाने का श्स्ताव वापस ले लिया। मुकुल रॉय ने लोकसभा में दिए बयान में कहा, 'एसी फर्स्ट और सेकेंड टियर में बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई है।' एसी फर्स्ट में 30 पैसे श्ति किलोमीटर और एसी सेकेंड में 15 पैसे श्ति किलोमीटर की बढ़ोतरी कायम रहेगी। इस बीच पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, 'अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो कें• की मनमोहन सरकार गिर जाती।' उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि मैंने मध्यावधि चुनाव टालने के लिए इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा, 'ममता बनर्जी को पहले से सब कुछ पता था, किराया तो सिर्फ बहाना था।'

- 39 गाड़ियों का विस्तार और 23 गाड़ियों के फेरे बढ़ेंगे
- कोलकाता मेट्रो में 2012–13 के दौरान 50 नई गाड़ियां चलाई जाएंगी।
- मुंबई उपनगर में 75 अतिरिक्त गाड़ियां, चेन्नई क्षेत्र में 18 और कोलकाता क्षेत्र में 44 नई उपनगरीय गाड़ियां चलेंगी।
- अर्जुन पुरस्कार विजेता राजधानी और शताब्दी में भी कर सकेंगे यात्रा।
- 'इज्जत योजना' के तहत यात्रा दूरी 100 से बढ़ाकर 150 किलोमीटर की।
- हर साल 10 खिलाड़ियों को मिलेगा 'रेल खेल रत्न' पुरस्कार।
- रेलवे में एससी/एसटी और ओबीसी के खली पद भरे जाएंगे।
- रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस अब 3,500 ट्रेनों को मार्ग सुरक्षा देगी।
- वर्ष 2012–12 में 102 करोड़ 50 लाख टन माल ढुलाई का लक्ष्य।
- रेलवे लाभांश भुगतान 6,676 करोड़ रूपए रहने का अनुमान।
- यात्री परिवहन वृद्धि 5.4 प्रतिशत, सकल यातायात राजस्व प्राप्ति। 1,32,552 करोड़ रूपए रहने का अनुमान। इस वर्ष के संशोधित अनुमान से 27.6 प्रतिशत वृद्धि।
- पहचान किए गए सभी 202 स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की स्थापना 2012–13 में पूरी होगी।
- रेलवे परिचालन अनुपात मौजूदा 95 प्रतिशत से सुधारकर 84.9 प्रतिशत का लक्ष्य।
- 2012–13 के लिए रेवले की अब तक की सर्वाधिक 60,100 करोड़ की योजना। इसमें 24,000 करोड़ रूपए की बजट सहायता।
- 2012–13 में 725 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए 6,872 करोड़ रूपए, 700 किलोमीटर लाइन के दोहरीकरण को 3,393 करोड़, 800 किलोमीटर अमान परिवर्तन के लिए 1,950 करोड़ रूपए और 1100 किलोमीटर विद्युतीकरण के लिए 823 करोड़ रूपए का प्रावधान।
- रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में साफ सफाई के लिए विशेष रखरखाव संस्था बनाई जाएगी।
- पेंट्री कारों और मुख्य रसोई के लिए जानी–मानी पेशवर एजेंसी की सेवाएं ली जाएंगी।
- यात्रियों को एसएमएस और इंटरनेट के जरिए गाड़ियों के चलने की सूचना के लिए ट्रेन सूचना प्रणाली शुरू होगी।
- 2012–13 में प्रस्तावित 84 स्टेशनों सहित कुल 929 स्टेशनों को उन्नत किया जाएगा। अब तक 490 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा चुका है। ■

यूपीए शासन काल में रेलवे की चहुंमुखी दुर्दशा आम आदमी हुआ बेहाल

2012–13 के रेल बजट पर भाजपा द्वारा 14 मार्च को जारी प्रेस वक्तव्य

जल बजट में वायदों की भरमार है, परन्तु उनके निभाने के नाम पर जीरो है। श्री अनिल काकोडर ने फरवरी 2012 में अपनी रिपोर्ट पर टिप्पणी देते हुए कहा था कि रेलवे की वित्तीय स्थिति 'ध्वस्त होने के कगार पर' लगी हुई है।

वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का विचार तक नहीं हुआ है, विगत के साथ कोई कड़ी तक नहीं जुड़ पाई है। जो कुछ भी विगत में घोषणाएं की गईं, उन्हें भुला दिया गया और योजनागत बनाम वास्तविक परफोर्मेंस के बारे में रिपोर्ट नहीं दी गई है।

पिछले वर्ष में केवल 236 आदर्श स्टेशनों में से केवल नौ स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ और अब इस बजट में ऐसे 85 और स्टेशनों की घोषणा कर डाली है, जिनके पूरे होने की संभावना दिखाई नहीं देती है। जिन 160 'मल्टीफंक्शनल काम्पलेक्सेज' को तैयार किया जाना था, उनमें से एक की भी तो स्थापना नहीं हो पाई है। आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति ने बहुत पहले फरवरी 2007 में बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरी शुरू करने की परियोजना और बिहार में ही मर्होवरा में डीजल यूनिट लगाने की परियोजना का अनुमोदन किया था जो आज तक तो कहीं नजर नहीं आ रही है। यहां तक के इन दोनों के ठेके भी किसी को सौंपे नहीं गए हैं। कांचरापाड़ा में रेल कोच फैक्टरी की घोषणा भी विलम्ब हो रहा है। रायबरेली में तीन महीने के अंदर रेल फैक्टरी का वायदा भी शुरूआती दौर में है।

जिन 133 नई रेलगाड़ियों की घोषणा की बात कही गई थी, उनमें से 30 से अधिक रेलगाड़ियां शुरू तक नहीं हुई हैं। 2009 में सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रूपए की त्वरित रेल विकास निधि भी बनाई नहीं गई है और इसके लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया है।

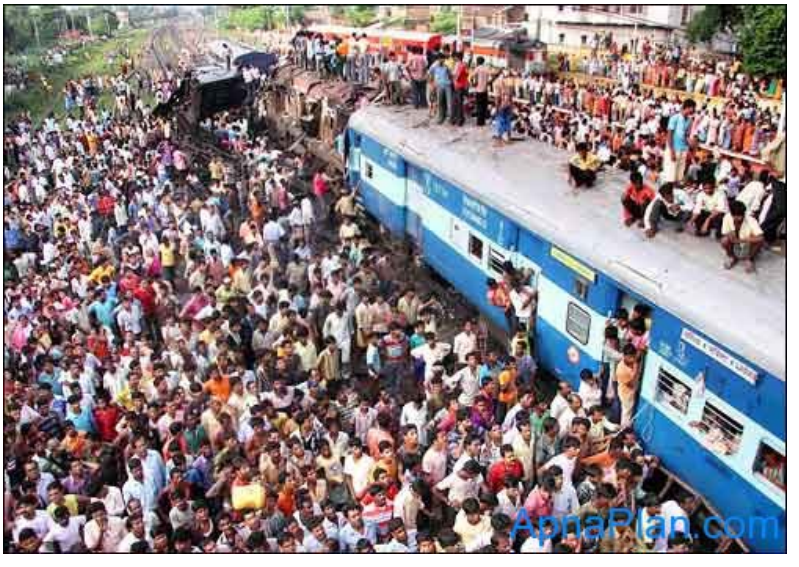

बजट 2011–12 में मेट्रो ट्रांसपोर्ट के लिए निर्धारित 6500 करोड़ रूप्ए की निधि का प्रस्ताव था और नवम्बर 2011 तक केवल 28 प्रतिशत (424 करोड़ रूपए) का ही इस्तेमाल हो पाया है।

यूपीए के अधीन 11वीं योजना के रेलवे प्रदर्शन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। 2007–12 की पांच वर्षों के अवधि में रेलवे के लिए 2,33,289 करोड़ रूपए स्वीकृत परिव्यय में से 30,356 करोड़ रूपए का लक्ष्य पूरा नहीं होने से इन पांच वर्षों की अवधि में केवल 202,933 करोड़ रूपए का इस्तेमाल हो पाएगा।

इस बजट में रेलवे सुरक्षा पर ध्यान देने बड़े–बड़े दावे किए गए हैं, परन्तु संसाधन जुटाने पर कोई स्पष्टता दिखाई नहीं पड़ती। 2010–11 में 374 लोगों की मृत्यु की भारी संख्या के बावजूद सरकार के सुरक्षा पर खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है। रेलवे सुरक्षा पर काकोदर समिति और रेलवे आधुनिकीकरण पर सैम पित्रोदा ने अगले पांच वर्षों में 660,000 करोड़ रूपए की संसाधन तुरंत जुटाने की बात कही है।

मंत्री महोदय का कहना है कि यात्री किराए में बढ़ोतरी मामूली सी है जबकि तथ्य यह है कि यात्री किराए से

राजस्व बढ़कर 28,000 करोड़ अर्थात् 28 प्रतिशत तक जा पहुंचेगा जिससे यह वर्तमान में 1,04,000 करोड़ रूपए हो जाएगा, जबकि यात्री ट्रेफिक की वृद्धि मात्र 5.4 प्रतिशत होगी। शेष 22 प्रतिशत यात्री किराये की वृद्धि दर्शाता है। यात्री किराए की बढ़ोतरी एक छलावा है। हिसाब लगाने से पता चलता है कि एसी1 और एसी2 के यात्रियों की यह बढ़ोतरी 10–12 प्रतिशत है, तो स्लीपर श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी के यात्रियों को 16 और 20 प्रतिशत अधिक देना होगा। इस प्रकार ज्यादह बढ़ोतरी का बोझ आम आदमी पर ही पड़ेगा।

मेट्रोपोलिटन उपनगरीय गाड़ियों में बेहद भीड़ होती है और गाड़ियां बहुत पुरानी है। 75 और गाड़ियों की वृद्धि से यह बोझ कम होने वाला नहीं है।

बजट से एक सप्ताह पूर्व सभी वस्तुओं पर रेलभाड़ा किराए की वृद्धि कर संशोधन किया गया था जिनमें खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ भी शामिल है। यह बढ़ोतरी 15 से 35 प्रतिशत तक की गई है जिससे सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत बुरी तरह से बढ़ जाएगी जिनमें नमक और चीनी भी शामिल है। स्पष्ट ही यह लोगों के साथ धोखा है कि ये घोषणाएं बजट का भाग नहीं बनाई गई। उच्च मुद्रास्फीति के युग में ये बढ़ोतरियां आम आदमी के जीवन को बेहद दुखी ही बनाएंगी।

यूपीए के 8 वर्षों के शासनकाल में रेलवे रक्तरंजित बनकर रह गई है। रेलवे की स्थिति एयर इण्डिया की राह पर जा रही है।

कार्यसंचालन दर 75 से बढ़कर 95 प्रतिशत तक जा पहुंची है। रेलमंत्री का वायदा है कि हम इसे 84 प्रतिशत तक ले आएंगे परन्तु कार्यकुशलता में सुधार कहां है.... यह कोई राकेट साईंस तो नहीं है कि यदि आप माल भाड़ा और यात्री किराया बढ़ा दे तो कार्यसंचालन दर गिर कर नीचे आ जाएगी।

सरकार को वास्तविक घरेलू संभावनाओं की समझ ही नहीं है। खान–पान सेवा क्षेत्र में ग्लोबल टेण्डरों का आमंत्रण किया गया है। क्या विदेशी लोग हमें वड़ापाव, डोसा और रसगुल्ला हमें परोसेंगे।

हाई स्पीड रेलवे कनेक्टिविटी की बात जबानी–जमा खर्च की तरह की जाती है क्योंकि इसके लिए जिस पूर्ण–व्यावहारिक अध्ययन की आवश्यकता है, वह कुछेक छोटे क्षेत्रों तक सीमित है। जबकि हम देखते हैं कि चीन ने तो पहले ही 2014 तक के लिए 28,000 कि.मी. नेटवर्क बना लिया है।

पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप की बड़ी चर्चा के बावजूद भी हमें प्राइवेट निवेशकों की भागीदारी में कोई खास प्रयास दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस मॉडल की हालत भी बेहद खराब है और रेल इंफ्रांस्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण करने के लिए कोई बड़ा निवेश किए जाने की संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। ■

पिछले वर्ष में केवल 236 आदर्श स्टेशनों में से केवल नौ स्टेशनों का आफ्रुनिकीकरण हुआ और अब इस बजट में ऐसे 85 और स्टेशनों की घोषणा कर डाली है, जिनके पूरे होने की संभावना दिखाई नहीं देती है। जिन 160 'मल्टीफंक्शनल काम्पलेक्सेज' को तैयार किया जाना था, उनमें से एक की भी तो स्थापना नहीं हो पाई है। आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति ने बहुत पहले फरवरी 2007 में बिहार के मफ्रोपुरा में इलेक्टिौक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरी शुरू करने की परियोजना और बिहार में ही महौंवरा में डीजल यूनिट लगाने की परियोजना का अनुमोदन किया था जो आज तक तो कहीं नजर नहीं आ रही है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का सचिन तेंदुलकर द्वारा 100वां शतक लगाने पर बधाई संदेश

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने एशिया कप में बांग्लादेश के विरुद्ध खेलते हुए सचिन तेंदुलकर द्वारा 100 वां शतक बनाने पर बधाई दी है। गत 16 मार्च, 2012 को अपने संदेश मे श्री गडकरी ने कहा कि निस्संदेह सचिन अब तक के महानतम किक्रेट खिलाड़ी हैं और पूरे राष्ट्र तथा दुनियाभर के खेलप्रेमियों द्वारा मनाए जा रहे इस उल्लास में भी अपने को शामिल करता हूं। ■

राजनीति किसलिए?

& çHkkr >k

तब सब दोषी हों तो एक दूसरे पर दोषारोपण कैसा? आज कोई निर्दोष रहना नहीं चाहता और जो रहना चाहता है उसे लोग रहने नहीं देते। जो आज दोषी नहीं हैं वो कल दोषी हो जाता है और जो निर्दोष है उसे लगता है कि कहीं मैं ही तो दोषी नहीं हूं। दोषयुक्त राजनीति का ऐसा दौर गत चार दशकों में कभी नहीं देखा गया। राजनीति फायदे की चीज है। राजनीति रुतबे की चीज है। राजनीति स्टेटस है। राजनीति–धूर्तता की पाठशाला है। राजनीति मद का आंगन है। राजनीति ईर्ष्या का परिसर है। राजनीति गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। राजनीति एक–दूसरे को गिराने का अखाड़ा है। राजनीति प्रतिशोध है। राजनीति धनबल और बाहुबल का पर्याय है। या फिर जनबल के अंतिम संस्कार का केन्द्र है, समझ में नहीं आ रहा। सत्ता में आना ही राजनीति है या राजनीति इसलिए कि सिर्फ सत्ता में आना है।

किसलिए राजनीति? किसके लिए राजनीति? क्यों राजनीति? इसकी समझ बिना अफ्रिकांश लोग आज भारतीय राजनीति में है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति कहने लगा है कि गरीबी मिटाना है तो राजनीति में चले जाओ, देश की नहीं स्वयं की! राजनीति राहत होनी चाहिए थी, लेकिन विडंबना देखिए कि जन–जन का मानस आज राजनीति से आहत है।

किसलिए राजनीति? किसके लिए राजनीति? क्यों राजनीति? इसकी समझ बिना अधिकांश लोग आज भारतीय राजनीति में है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति कहने लगा है कि गरीबी मिटाना है तो राजनीति में चले जाओ, देश की नहीं स्वयं की! राजनीति राहत होनी चाहिए थी, लेकिन विडंबना देखिए कि जन–जन का मानस आज राजनीति से आहत है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अंग्रेजों को भगाने वाले का सामर्थ्य रखने वाले भारतीय ही तो थे। आखिर किन कारणों से अंग्रेजों को भगाने में भारतीय सफल रहे। कैसे हमने आजादी प्राप्त की? क्या सिर्फ आजादी प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य था? आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिकांश लोगों को ठीक से दो जून का खाना भी मयस्सर नहीं है। हमारे सपने क्यों धूमिल हो गए?

क्यों महरूम है आज आजादी की लड़ाई की उस जुनून से, जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। क्या आज उस जूनून की आवश्यकता नहीं है? जब हम अंग्रेजों को भगा चुके तो भारत में वर्तमान राजनीति की दशा को नहीं बदल सकते? ऐसे एक नहीं अनेक सवाल उत्तर की आशा में पूरे देश में अनेक लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। स्थितियां इतनी दयनीय हो गई है कि कोई ताल ठोककर नहीं कह सकता कि मैं राजनीति कर रहा हूं। नेता और राजनीति इस धरा पर लज्जाजनक शब्द हो गया है। किसी का उपहास उड़ाना हो तो कह दीजिए– नेताजी हैं; राजनीति करते हैं। उसे गाली देने की कोई जरूरत नहीं। 65 वर्षों में नेता और राजनीति गाली का पर्याय बन जाये इससे दुःखद अध्याय भारतीय राजनीति का और क्या हो सकता है? भारत सबका है सब भारत के हैं। हर दल के संविधान में इस बात को लिखा गया है कि उनका दल देश की उन्नति के लिए काम करेगा पर कितने लोग हैं आज जो अपनी पार्टी की नीति और सिद्धांत को लेकर काम करते हैं। हर दल की विचारधारा लचर हो गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आजादी वाली कांग्रेस आजादी के बाद 65 वर्षों में सोनिया गांधी तक पहुंच जाती है और स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि लोग महात्मा गांधी को भूल जाते हैं और सोनिया गांधी से जुड़ नहीं पाते। गांधी शब्द की ऐसी दुर्दशा किसने की? क्यों की? क्या करना चाहिए था? क्या कांग्रेस में इस बात पर कोई विचार कर रहा है? कितनी विडंबना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास प्रचार करने वालों के नाम पर

सिर्फ पार्टी नहीं परिवार ही बचा है? स्थिति यह हो गई कि दोनों राज्यों में परिवार की पोल खुल गई। न सोनिया चली, न राहुल। दुर्गति के अंतिम हाशिए पर आने के बाद भी सोनिया जी और राहुल जी के मुंह से यह न निकले कि अब हम कांग्रेस अध्यक्ष और महामंत्री पद पर नहीं रहना चाहते तो गलती किसकी कही जाएगी? दूसरों में नैतिकता की तलाश वही कर सकता है जिसने अपनी जिंदगी को नैतिकता से तराशा हो। मजेदार मामला यह भी है कि मां–बेटे इस्तीफा दे नहीं रहे और परिवार में विलीन हो चुकी पार्टी का कोई सदस्य ऐसा नहीं बचा जो दबी जुबां से इस्तीफा मांग सके। दूसरे दलों पर गरजते शेर अपने दल में पता नहीं क्यों गीदड़ों की भूमिका में आ जाते हैं। सच को रखने का साहस जो दल और व्यक्ति खो देता है वह झूठ के पैबंद से अपने शरीर की और संगठन की नग्नता नहीं छुपा सकता।

कांग्रेस तो कांग्रेस अन्य दलों में कुछ हद तक भाजपा को छोड़ दें तो शायद राजद के लालू को गैर–राजनीतिक रह चुकी अपनी पत्नी पर जितना विश्वास था शायद अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं, यही कारण था कि भरे सदन में चौके में गृहणी की भूमिका निभा रही को सभी कार्यकर्ताओं को लतियाते हुए बिहार की बागडोर सौंप दी और दल के किसी व्यक्ति ने चूं तक नहीं की। लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? खुद चारा घोटाला के लिए गुनाहगार तो पत्नी को बना दिया बिहार की पहरेदार। क्या लोकतंत्र में सच नहीं बोलना चाहिए? आखिर गृहिणी की भूमिका में रहने वाली राजनीति में ककहरा तक नहीं जानने वाली जब बिहार की बागडोर संभालेगी तो क्या बिहार का विकास होगा? क्यों नहीं उस समय इस सच को बोला गया। जब अपने बारे में अधिक और प्रांत व देश के बारे में कम सोचने की स्थिति बन जाती है और संघर्ष का माद्दा समाप्त हो जाता है और कुर्सी के मोह में फंस जाते हैं तो हालात ऐसे ही बनते हैं। बात करें सपा की तो देखिए न, मुलायम हटे, अखिलेश आए। क्या इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे या लोहिया का समाजवाद? समाजवाद की यह नई परिभाषा जो परिवारवाद में बदल गई और सबके सब समाजवादी मौन हैं। आखिर कौन करेगा रखवाली जनतंत्र की? लोकतंत्र में राजवंश की यह नई परंपरा हमें कहां ले जाएगी? किस मुंह से कोसेंगे मुलायम जी और लालू जी कांग्रेस के परिवारवाद को। आखिर किससे कहा जाए? बात करें बसपा की? वहां तो कोई लोकतांत्रिक काम ही नहीं। वहां जो कुछ भी है 'मायातांत्रिक' है। वहां मुंह से निकला शब्द ही फैसला होता है। चर्चा का बसपा में कोई स्थान नहीं। स्वामी और नौकर की भूमिका का स्थान ले चुकी है बसपा। वहां मायावती स्वामी है और बाकी नौकर हैं और जो नौकर की भूमिका में नहीं रहता है उसे जोकर बना दिया जाता है। बसपा में झूठ तो झूठ है ही पर सच भी झूठ है।

यह लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक स्थिति है। दलितों की काया पर बैठी माया हीरा और पन्ना से स्वयं के शरीर को जड़ लेती है पर लोकतंत्र वहां तार–तार हो जाता है। दलित नेता का ऐसा पाश्चात्य स्वरूप और मायावी रूप भारत ने कभी नहीं देखा। डीएमके और एआईएडीएमके का भी यही हाल है। ये दोनों पार्टियां किसलिए कर रही हैं राजनीति, किसी के समझ में नहीं आता? अरबों–खबरों की संपत्ति से जुड़ी जिंदगियां क्या गरीबों की सिसकियां समझ पाएंगी? 2जी स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों से जुड़े लोगों से जनता सत्ता जरूर छीन लेती है पर डीएमके अपनी आदत से बाज नहीं आती। गरीबों को बरगलाना इनकी आदत है। ये दोनों दल श्रद्धा को एनकैश करते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि लोकतंत्र तमिलनाडु में सिमट गया है। यहां महती आवश्यकता है दोनों ही दलों को दरकिनार कर एक नए संघर्ष की राह पर चलने की ताकत जिस दल में हो, जो दल पीढ़ियां–दर–पीढ़ियां खपाने को तैयार हो, उसे वहां पर आगे जाना होगा। जब अकेली ममता बनर्जी कॉमरेडों के गढ़ में ममता की बयार बहा सकती है तो फिर करुणानिधि और जयललिता में उलझी राजनीति को कोई सही रास्ते पर क्यों नहीं ला सकता? वहां भी जरूरी है एक ममता बनर्जी की, जो सतत् संघर्ष करे और संघर्ष तब तक

विचारफ्राराओं का ऐसा हश्र पूर्व में नहीं देखा गया। प्रतिबद्धता शब्द की माली हालत ठीक नहीं है। प्रतिबद्ध और अनुबंफ्रा की पवित्रता पर नित्य चोट हो रहा है। जो प्रतिबद्ध है वह टूट नहीं सकता। अतः नित्य टूटने वाले और बिकने वालों की बोली लग रही है। लोग फ्राड़ल्ले से बिक रहे हैं। विचारों की आड़ में बाजार और मंड़ी चला रहे हैं। जो अनुबंफ्रित हैं वह अनुबंफ्रा तोड़ नहीं सकता, अतः वह पीछे की कतार में अपने अनुबंफ्रित फ्रार्म को लिए खड़ा है और जो नित्य मर्यादाओं को तोड़ते हैं वे पूरी तरह आगे आने में सफल हो रहे हैं।

जब तक परिणाम न आए। किस–किस की बात करें? आंध्रप्रदेश या जम्मू–कश्मीर की, कहानी एन.टी. रामाराव की हों, फारूख अब्दुल्ला की हो या उड़ीसा के स्व. बीजू पटनायक की हो, ये वो दल हैं जिसके पास सोमवार है न मंगलवार, बुधवार है न गुरूवार, न शुक्रवार है न शनिवार और न ही रविवार और है तो सिर्फ परिवार। सातों वार से बढ़कर यदि परिवार ही हो जाए तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या होंगे? परिवारवाद की अंधी गलियों में लोकतंत्र भटक रहा है। जिन दलों की हमने चर्चा की है उन दलों में कार्यकर्ताओं की भूमिका या तो कर्मचारियों की तरह या फिर भारतीय राजनीति में चमचों की तरह हो गई है। जो जिस व्यक्ति के निकट है उस व्यक्ति के भविष्य से ही राजनीति जुड़ी है। विचारधाराओं का ऐसा हश्र पूर्व में नहीं देखा गया। प्रतिबद्धता शब्द की माली हालत ठीक नहीं है। प्रतिबद्ध और अनुबंध की पवित्रता पर नित्य चोट हो रहा है। जो प्रतिबद्ध है वह टूट नहीं सकता।

अतः नित्य टूटने वाले और बिकने वालों की बोली लग रही है। लोग धड़ल्ले से बिक रहे हैं। विचारों की आड़ में बाजार और मंड़ी चला रहे हैं। जो प्रतिबद्ध हैं वह प्रतिबद्धता तोड़ नहीं सकता, अतः वह पीछे की कतार में अपनी प्रतिबद्धता धर्म को लिए खड़ा है और जो नित्य मर्यादाओं को तोड़ते हैं वे पूरी तरह आगे आने में सफल हो रहे हैं।

भारत के राजनीतिक दलों का जो स्वरूप बना है उसमें भाजपा अभी भी सबसे अलग दिख रही है। वो चाहे तो भारतीय राजनीति की अंतर्रात्मा की प्रतीक बन सकती है। वो जन–गण–मन का पर्याय बन सकती है। वो लोकतंत्र की सच्ची सपूत बन सकती है। उसके लिए ऐसा सुनहरा अवसर नियति ने प्रदान किया है। उसे कुछ नहीं करना है, उसे तो सिर्फ आजादी के पूर्व वाली कांग्रेस की भूमिका में आना है। सत्य, अहिंसा और निष्ठा के मार्ग पर अपने दल को, अपने कार्यकर्ताओं को आगे लेते जाना है। भाजपा को उन चीजों से वंचित रहना होगा, जिन कारणों से कांग्रेस धूल–धूसरित हो रही है। उत्सवी भाव छोड़कर अगर संघर्षीय भाव धारण करे, लोकतंत्रीय पद्धति के साथ–साथ जमीनी हकीकत को समझने का भरसक प्रयत्न करें तो शायद 6 अप्रैल 2012, हमारी स्थापना का 32वां वर्ष, सफलता के नए सोपान तय करने की दिशा में अगुआई करेगा। ईश्वर प्रदत्त अवसर को यदि हमने अपने परिश्रम और पराक्रम से जीतने की कोशिश की तो शायद नियति भी हमारा साथ देगा और हम 'अंत्योदय और सर्वोदय' का अरूणोदय करने में सफल भूमिका निभा सकेंगे। भाजपा के बारे में कहा जाता है यह नेताओं की नहीं, व्यापारियों की नहीं, सरमाएदारों की नहीं, पूंजीपतियों की नहीं, नाजिरशाहियों की नहीं, सामंतों की नहीं, यह सर्वसाधारण कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें हर साधारण भारतीय काम कर सकता है, जिसको भारत से, भारतीयता से और भारतमाता से प्यार हो। ■

(लेखक मध्यप्रदेश भाजपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य हैं)

भाजपा नेता नरेंद्र मोदी प्रतिष्ठित पत्रिका 'टाइम' के मुखपृष्ठ पर

गुजरात में विकास की गंगा बहाने को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चहुंओर प्रशंसा हो रही है। चाहे योजना आयोग के दस्तावेज हो या फिर प्रधानमंत्री के भाषण, इंडिया टुडे पत्रिका की रिपोर्ट हो या फिर राजीव गांधी फाउंडेशन की रिपोर्ट, सभी जगह श्री मोदी की कुशल कार्यप्रणाली की प्रशंसा की जाती रही है। अभी हाल में ही प्रतिष्ठित प्रत्रिका 'टाइम' ने अपने मुखपृष्ठ पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्रिका ने श्री मोदी को अपने 26 मार्च के एशिया संस्करण के कवर पर जगह दी है। पत्रिका के कवर पर 'मोदी मतलब कामकाज लेकिन क्या वह भारत का नेतृत्व कर सकते हैं' शीर्षक के साथ श्री मोदी की तस्वीर प्रकाशित की गई है।' टाइम के अनुसार, '...एक वर्ग जब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचता है कि जो देश को भ्रष्टाचार के दलदल और निकम्मेपन से उबार सकता हो, एक ऐसा नेता जो देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हुए चीन की बराबरी पर ला दे तो निश्चित रूप से मोदी का नाम आता है।' ■

रेल बजट : वायदे ज्यादा, काम कम

& ih;"k xk;y

यूपीए शासन के 8 वर्षों में भारतीय रेल को एक दिवालिया संगठन के रूप में तबदील कर दिया गया है, जिसकी आधारभूत संरचना चरमरा गई है, जिसका संरक्षा रिकार्ड बहुत खराब है। फरवरी, 2012 की अपनी रिपोर्ट में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री अनिल काकोदकर ने यह टिप्पणी की है कि रेलवे की वित्तीय स्थिति लगभग चरमरा गई है। यूपीए सरकार भारतीय रेल को उसी तरह से बर्बाद कर रही है, जिस तरह से उन्होंने एयर इण्डिया को बर्बाद किया।

रेल मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट एक भ्रामक बजट है, जिससे देखने पर प्रतीत होता है कि यह सुधारवादी है, परन्तु वास्तव में यह विसंगतियों से भरा हुआ है और आम आदमी को दुःख और पीड़ा पहुंचाने वाला है।

भाड़े और यात्री किराये में वृद्धि

बजट से एक सप्ताह पूर्व अनाज, उर्वरक, सीमेंट, कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों सहित सभी वस्तुओं पर भाड़े की दरें बढ़ाई गई थीं। यह वृद्धि 15–35 प्रतिशत के बीच है, जिसके कारण नमक और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायेंगी। रेलवे को 2012–13 में भाड़ा राजस्व में 30 प्रतिशत की वृद्धि की आशा है और उस संबंध में 89,393 करोड़ रूपये है। यदि सामान की मात्रा

में 10 प्रतिशत की भी वृद्धि होती है, तो इससे भाड़ा दरों में औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बजट से ठीक पूर्व की गई ऐसी घोषणाएं अनैतिक हैं।

यात्री किरायों में वृद्धि की घोषणा करते समय मंत्री ने सभी प्रकार की वृद्धि को पैसों को प्रति किलोमीटर आधार में बदला है और ऐसा आभास कराया है कि यह केवल नाममात्र की वृद्धि है। परन्तु विस्तार में जाने से समस्या का पता चलता है। आंकड़ों का जरा ध्यान से विश्लेषण करने से पता चलता है कि यात्री किराये में भारी वृद्धि की गई है। रेलवे को 2012–13 में यात्री राजस्व में 28,360 करोड़ रूपये की वृद्धि होने की आशा है, जो बढ़कर 1,32,555 करोड़ रूपये हो जायेगा। यह वृद्धि 27.2 प्रतिशत बैठती है। यात्री संख्या में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। अतः 21.8 प्रतिशत का शेष स्पष्ट रूप से यात्री किराये में वृद्धि है और इससे भी खराब बात यह है कि उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिए वृद्धि लगभग 12 प्रतिशत है, जबकि आम आदमी, जो स्लीपर और सामान्य श्रेणी में यात्रा करता हे, को 20–40 प्रतिशत के बीच अधिक किराया देना होगा। मुम्बई के उपनगरीय यात्री सबसे अधिक प्रभावित होंगे। यह यात्री किराया बढ़ाने का सर्वाधिक गलत तरीका है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए।

बजट से एक सप्ताह पूर्व अनाज, उर्वरक, सीमेंट, कोयला और पेटौलियम उत्पादों सहित सभी वस्तुओं पर भाड़े की दरें बढ़ाई गई थीं। यह वृद्धि 15–35 प्रतिशत के बीच है, जिसके कारण नमक और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायेंगी। रेलवे को 2012–13 में भाड़ा राजस्व में 30 श्तिशत की वृद्धि की आशा है और उस संबंफ्रा में 89,393 करोड़ रूपये है। यदि सामान की मात्रा में 10 श्तिशत की भी वृद्धि होती है, तो इससे भाड़ा दरों में औसतन 20 श्तिशत की वृद्धि होगी। बजट से ठीक पूर्व की गई ऐसी घोषणाएं अनैतिक हैं।

परिचालन अनुपात

परिचालन अनुपात (लागत बनाम आय अनुपात) वित्त वर्ष 2008 में 75.9 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2011 में 95 प्रतिशत हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि रेलवे मूल सफाई और यात्री सुविधाओं में सुधार नहीं कर पाई है और रेकों, कोचों और स्टेशनों का कुशल एंग से रखरखाव करने में भी असफल रही है। रेलगाड़ियां लगातार विलम्ब से चल रही हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, पूंजी निवेश लगभग ठप्प हो गया है और रेल

आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाने, सिग्नल प्रणाली सुधारने, रेल फाटकों का प्रबन्धन और तेज गति वाला रेल नेटवर्क बनाने संबंधी सभी योजनाएं केवल कागजों पर बनी रह गई हैं। सरकार बेहतर परिचालन पर ध्यान देने के बजाय किरायों को बढ़ाकर अपनी अकुशलता के लिए उपभोक्ताओं पर बोझ डालना चाहती है।

पिछले वायदों को पूरा करने में पूर्ण विफलता

गत वर्षों में रेल बजट में घोषित की गई परियाजनाओं को लागू करने में भारी विलम्ब हुआ है। 20 वर्ष पहले घोषित की गई परियोजनाएं आज तक लागू नहीं की गई हैं। ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं, जिनमें व्यवहार्यता अध्ययन भी पूरे नहीं हुए हैं, भूमि अर्जन शुरू नहीं हुआ है और बजटीय आबंटन इतना कम हैं, जिसके कारण भारी विलम्ब और लागत वृद्धि हुई है। गत वर्ष घोषित 236 आदर्श स्टेशनों में से केवल 9 का आधुनिकीकरण हुआ है और इस बजट में ऐसे अनेक अतिरिक्त स्टेशनों की घोषणा की गई है। 160 बहु–उद्देशीय काम्प्लेक्सों, जिनकी स्थापना की जानी थी, में से एक भी अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

यहां तक कि बिहार में मधेपुरा में एक विद्युत लोकोमोटिव फैक्टरी यूनिट लगाये जाने की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं, जिन्हें आर्थिक कार्यों के कैबिनेट समिति ने फरवरी 2007 में स्वीकृति प्रदान की थी, के लिए ठेके भी अभी तक नहीं दिये गये हैं। कांचरापाड़ा में प्रस्तावित रेल कोच फैक्टरी स्थापित करने में भी असाधारण विलम्ब हुआ है। राय बरेली में 3 महीने में स्थापित की जाने वाली फैक्टरी अभी भी निर्माणाधीन चरणों में है। फिर भी मंत्री मध्यप्रदेश और केरल में नये संयंत्र लगाने की घोषणा करते है, जबकि इस संबंध में ग्राउंडवर्क अपर्याप्त है और फंड की कोई योजना नहीं है।

संरक्षा

मंत्री ने स्पष्टरूप से संरक्षा पर जोर दिया है और इस संबंध में बड़े–बड़े वायदे किये हैं। संरक्षा मोर्चे पर रेलवे का पिछला रिकार्ड बहुत ही निराशाजनक रहा है। विशेष रेलवे संरक्षा निधि, जिसमें 2001 से अब तक 17,000 करोड़ रूपये निवेश किये गए हैं, से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। काकोदर समिति की रिपोर्ट के अनुसार संरक्षा पहलू को ध्यान में रखे बिना अधिक से अधिक रेलगाड़ियां विद्यमान 'ओवरलोडिड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में बढ़ाई जा रही हैं, जिसके कारण भारी क्षति हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। कैग ने रेलवे के अपने कार्य निष्पादन आडिट में प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं और तुरंत सुधारात्मक कदम, जैसे कि संरक्षा प्रतिष्ठानों का आडिट, उठाने का सुझाव दिया है। बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर अभी भी भारी संख्या में लोग मारे जाते हैं और गाड़ियों के आपस में टकराये जाने को रोकने संबंधी उपकरण, जिनके बारे में वायदा किया गया था, अभी भी नहीं लगाये गये हैं। संरक्षा इस सरकार के लिए अभी भी चर्चा का शब्द बना हुआ है और इस महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए ईमानदारीपूर्ण कोई प्रभाव नहीं किये गये हैं।

रेलवे को तुरंत एक विज़ीनरी नेतृत्व की और कुप्रशासन, भ्रष्टाचार एवं पुरानी तकनीक से प्रभावित इस बीमार संगठन को स्वस्थ बनाने के लिए एक रोडमैप की आवश्यकता है। कुशलता बढ़ाने, आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाने और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए तरीकों पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। परन्तु एक ऐसी निष्प्रभ सरकार से इस प्रकार की आशा करना बेकार होगा, जो चुनावी हार एवं हठी सहयोगी दलों, जो सभी ओर से सरकार की खींच–तान में लगे हुए हैं, के दबाव में लड़खड़ा रही है।

महाराष्ट्र और मुम्बई में उपनगरीय सेवाएं

महाराष्ट्र भारत में बड़े राज्यों में एक राज्य है। गत कई वर्षों से महाराष्ट्र में रेलवे नेटवर्क की भारी उपेक्षा की गई है। मुम्बई भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व देने वालों में से एक है, परन्तु उसके साथ सदैव सौतेला व्यवहार किया गया है। मंत्री जी ने मुम्बई में 75 नई सेवाओं की घोषणा की है, जो भारत की आर्थिक राजधानी की निरंतर बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह से अपर्याप्त है। इसके विपरीत सेवा की गुणवत्ता दिन–प्रतिदिन गिरती जा रही है और गाड़ियों में भारी भीड़ के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इन सबके बाद किरायों में भारी वृद्धि की गई है।

विजन की कमी

रेलवे को तुरंत एक विज़ीनरी नेतृत्व की और कुप्रशासन, भ्रष्टाचार एवं पुरानी तकनीक से प्रभावित इस बीमार संगठन को स्वस्थ बनाने के लिए एक रोडमैप की आवश्यकता है। कुशलता बढ़ाने, आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाने और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए तरीकों पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। परन्तु एक ऐसी निष्प्रभ सरकार से इस प्रकार की आशा करना बेकार होगा, जो चुनावी हार एवं हठी सहयोगी दलों, जो सभी ओर से सरकार की खींच–तान में लगे हुए हैं, के दबाव में लड़खड़ा रही है। ■

¼y[kd tku&eku pkVMZ vdkmUVsV] jkT;lHkk lnL; o Hkktik d jk"Vh; dk"kk/;{k gS½

आम बजट 2012&13 की मुख्य बातें

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 16 मार्च 2012 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2012–13 प्रस्तुत किया। पांच राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद लोगों को उम्मीद थी कि सरकार कुछ सबक लेगी लेकिन उसने जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। इस बजट की चहुंओर आलोचना हो रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बजट जनविरोधी है तो उद्योग जगत ने भी इसे निराशाजनक बताया है। आम आदमी बजट में सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा था लेकिन बजट में देश की 70 प्रतिशत जनता को सबसे अधिक निराश हुई है और वह ठगा सा महसूस कर रहा है। इस बजट में आयकर की सीमा मामूली बढ़ाकर सरकार ने लोगों के हाथों में लालीपाप थमाया है। सेवा कर और अन्य मदों में जिस हिसाब से वृद्धि की गई है उससे देश की जनता पर 40 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे उनकी कमर टूट जाएगी। देश में जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चारों ओर महंगाई बढ़ रही है, वहीं बजट में आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम किया गया है। पाठकों की जानकारी के लिए हम यहां आम बजट 2012–13 के प्रमुख बिंदु प्रकाशित कर रहे हैं:

- बिजली, एयरलाइन, सड़क एवं पुल, पोर्ट, किफायती आवास, बांध तथा उर्वरक संयंत्रों का निर्माण करने वाली कंपनियों के विदेशी वाणिज्यिक कर्ज (ईसीबी) की ब्याज अदायगी पर लगने वाले विदहोल्डिंग टैक्स को 20 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया
- अस्पताल, कोल्ड चेन, वेयरहाउस, किफायती आवास व उर्वरक संयंत्रों में पूंजीगत खर्च पर निवेश संबंधी डिडक्शन की सीमा 100 से बढ़ाकर 150 प्रतिशत की गई।
- रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी) वाले संयुक्त उद्यम विकसित करने के लिए दिशानिर्देश जारी।
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्थापित करने के पिछले बजट के वादे के तहत 8000 करोड़ के प्रारंभिक कोष वाला पहला इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित
- राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग नीति के तहत जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने तथा 10 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे देश भर में राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण प्रक्षेत्रों (नेशनल इंवेस्टमेंट एंड मैन्यूफैक्चरिंग जोंस) की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

बिजली

- 31 मार्च 2013 तक स्थापित नए बिजली संयंत्रों को 10 साल तक मुनाफे के 100 फीसदी डिडक्शन की सुविधा।
- घरेलू बिजली कंपनियों को दो साल (मार्च 2014) तक कोयला, प्राकृतिक गैस एवं एलएनजी के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्ति। कोयले के आयात पर सीवीडी में भी एक प्रतिशत की रियायत।

सड़क

- अभी तक केवल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजमार्गो का निर्माण करने वाले सरकारी ठेकेदारों को चुनिंदा उपकरणों के आयात पर आयात शुल्क नहीं देना होता था। अब यह सुविधा शहरी सड़कों तथा उन्हें बनाने वाले नगर विकास प्राधिकरणों के कांट्रैक्टर्स को भी मिलेगी। टनेल बोरिंग मशीनों के आयात पर शुल्क छूट के लिए एंड–यूज की शर्त हटी।
- सड़क निर्माण में पीपीपी को बढ़ावा देने व टोल प्लाजा के रखरखाव व संचालन करने वाली कंपनियों को ईसीबी जुटाने की छूट।

विमानन

- विदेशी एयरलाइनों को भारतीय एयरलाइनों में 49 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की छूट देने पर सरकार विचार कर रही है।

औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर

- पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के दोनों ओर दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर का विकास प्रगति पर है। सितंबर, 2011 में इसके लिए 18,500 करोड़ की केंद्रीय सहायता पांच वर्ष के लिए मंजूर की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान ने भी 4. 5 अरब डॉलर की भागीदारी का एलान किया है।

आवास

- कम लागत की आवासीय इकाइयों को ईसीबी जुटाने की अनुमति
- ग्रामीण आवास निधि (रूरल हाउसिंग फंड) के लिए प्रावधान 3000 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ किया गया।
- 25 लाख रुपये तक के मकानों के लिए 15 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज दर में 1 फीसदी की छूट एक साल के लिए और बढ़ी। ■

लेखा-जोखा के विवरण के अलावा और कुछ नहीं

v#.k tsVyh] urk çfri{k ¼jkT; lHkk½

bस बजट में यूपीए सरकार द्वारा गलती न किये जाने का एकमात्र तरीका अवसर को गंवा देना और कुछ नहीं करना था। और उसने ऐसा ही किया। इसने इस बजट को एक ऐसी कवायद न मानने का फैसला किया जिससे नीति की दिशा बदले बल्कि इसे लेखा–जोखा का मात्र एक विवरण बना दिया। स्पष्टतया, इसमें अर्थ–व्यवस्था सम्बंधी भावना है। निवेश में गिरावट है। विदेशी निवेश धीरे–धीरे कम हो गया है। यहां तक कि निवेशक भी देश से बाहर बेहतर निवेश मुकाम तलाश रहे हैं। कोई भी वित्त मंत्री इस भावना को बदलना चाहेगा। सरकार हाल के विधान सभा चुनावों के बाद निराश है। नेतृत्व का मनोबल गिरा हु आ है। बजट कुछ सकारात्मक कदम उठाने और अपने कार्य कर्ता ओं का मनोबल बढ़ाने का एक ऐतिहासिक अवसर था। परन्तु वित्त मंत्री ने इस अवसर का फायदा उठाना उचित नहीं समझा। वह सरकार को किसी प्रतिकूल टिप्पणी से बचाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कोई महत्वपूर्ण कदम न उठाने का निर्णय लिया।

उनके लिये दो रास्ते खुले थे। 1991 के बाद का तरीका अर्थ–व्यवस्था को और अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाना था। अधिक तर्कसंगत कराधान, सड़कों में निवेश, बेहतर बुनियादी ढांचा, अधिक सु धार, अधिक निवेश को आकर्षित करना, निश्चितरूप से इन सबके लिए वित्त मंत्री के लिये एक महत्वपूर्ण रास्ता खुला था। उन्होंने इस भलीभांति परखे एवं जांचे हुए रास्ते को न चुनने का निर्णय लिया। उन्होंने उच्च कराधान और भारी सरकारी खर्च वाला 1991 से

पूर्व का रास्ता अपनाया–यह एक ऐसा कदम है जो अर्थ–व्यवस्था को अधिक मंदी और गैर–प्रतिस्पर्धात्मक बनायेगा।

उन्होंने उत्पाद–शुल्क में 2 प्रतिशत की वृद्धि की। उन्होंने सेवा कर का दायरा बढ़ा दिया और कर स्लैब में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। उन्होंने अनेक अन्य एन्ट्रीज में भी छेड़छाड़ की और हाल के बजटीय इतिहास में सबसे अधिक करों का बोझ लाद दिया।

इस उच्च कराधान का प्रभाव वास्तव में अर्थ–व्यवस्था पर बुरा पड़ेगा। बुनियादी ढांचे को विदेशी वणिज्यिक ऋण अथवा कर–मु क्त बांडों के माध्यम से मजबूत बनाया जा सकता है। बजट में सर्वाधिक चिन्ताजनक आंकड़े हैं – 5.9 प्रतिशत राजकोषीय घाटा। ये आंकड़े भी कमतर बताये गये प्रतीत होते हैं क्योंकि सब्सिडी बोझ सम्बंधी आंकड़ों की इसमें झलक नहीं मिलती। भारी कराधान की खुराक देने के बाद और इस आशा के साथ कि विस्तारित अर्थ व्यवस्था से उन्हें अधिक वसूलियां मिलेंगी, वित्त मंत्री ने 45, 547 करोड़ रूपये का उच्च कारपोरेट कर, 23, 907 करोड़ रूपये का उच्च आयकर, 33964 करोड़ रूपये का उच्च उत्पादन शु ल्क और 29, 000 करोड़ रूपये का उच्च सेवाकर इन सब में शामिल किया है।

आम आदमी पर इस भारी बोझ के बावजूद, उन्होंने राजकोषीय घाटे को इस काल्पनिक धारणा के आधार पर 5.1 प्रतिशत रखा है कि अगले वर्ष में सब्सिडी कम हो जायेगी। वास्तव में 2011–12 के लिये वास्तविक सब्सिडी बोझ 2011 के बजट अनुमानों की तुलना में 73, 000 करोड़ बढ़ गया है जोकि बहुत अधिक है। यदि खाद्य सुरक्षा विधेयक के अतिरिक्त प्रभाव को खाते में न भी जोड़ा जाये, तो आगामी वर्ष में राजकोषीय घाटे का वास्तविक बोझ काफी अधिक हो सकता है। रक्षा क्षेत्र उपेक्षित रहा है। रक्षा उपकरणों के लिये आवंटन में मामूली वृद्धि वर्ष में होने वाली मुद्रास्फीति से समाप्त हो जायेगी एक बार सरकार 4,79,000 करोड़ रूपये के ऋृण लेने के लिये मार्किट जाती है, तो निजी क्षेत्र का मार्किट से बाहर होने का पूरा–पूरा खतरा है।

सरकार की महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की महत्वपूर्ण योजना का कार्य–निष्पादन इस वर्ष निराशाजनक रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार ने आगामी वर्ष में नरेगा आवंटन में 7,000 करोड़ रूपये की कटौती की है। आर्थिक नीति निर्धारण और इसके क्रियान्वयन के लिये स्पष्टता, नेतृत्व और वृहत आम सहमति का होना जरूरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने उस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है।

यदि सरकार जीवंत और संघर्षरत रहना चाहती है तो उसे कुछ न करने का रवैया छोड़ना होगा। ■

¼lkHkkj % n fgUnw½

प्रणब का वर्तमान बजट मुद्रास्फीति और महंगाई का बजट : राजनाथ सिंह

2012–13 के केन्द्रीय बजट पर पूर्व भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा 16 मार्च को प्रस्तुत टिप्पणी

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किया गया 2012–13 का केन्द्रीय बजट भारत के लोगों के लिए अत्यंत निराशाजनक रहा है। बजट से उम्मीद की जा रही थी कि यह सुस्त अर्थव्यवस्था के लिए सुधार लाने के दिशा में कार्य करेगी परन्तु पूरा प्रयास ही हमारे सामने एक गवाए गए मौके के रूप में उभर कर सामने आया है।

उत्पाद शुल्क और सेवाकर में बढ़ोतरी से बजट बढ़ाने वाली मुद्रास्फीति की सम्भावनाएं पैदा कर रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार दावा किया था कि मुद्रास्फीति को अगले राजकोषीय वर्ष में नियंत्रित कर लिया जाएगा, परन्तु बजट के प्रस्तावों से तो मुद्रास्फीति बढ़े ही बढ़ेगी।

आम आदमी के लिए बढ़ती अपार कीमतों से उसकी क्रय शक्ति पर पहले ही आंच आ चुकी है और सरकार आम आदमी के लिए किसी प्रकार की राहत देने में विफल रही है। बजट में साइकिल पर भी उत्पाद शुल्क के बढ़ने के प्रस्ताव से तो आम आदमी के आने जाने का साइकिल वाला साधन भी अछूता नहीं रहा है।

एक तरफ, सरकार सेवा कर में 10 से 12 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव करती है तो दूसरी तरफ उसने छूट सीमा में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं की है। उच्च सेवा कर दरों की वृद्धि से आम आदमी के खर्चे हर तरफ बढ़ जाएंगे और एक बार फिर से लोगों का घरेलू बजट मुद्रास्फीति निगल जाएगा।

सड़क का आम आदमी आय सीमा को 1,80,000 रूपए से बढ़ाकर नाम मात्र के 2,00,000 रूपए करने से बेहद निराश है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 2008 की संकटपूर्ण स्थिति तक पहुंच गया है। सरकार पहले ही वर्तमान राजकोषीय वर्ष में 130 आधारभूत अंक पर अपना राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से वंचित हो चुकी है। यदि सरकार इसी तरह धीमे विकास और सुस्त निवेश में लिप्त रहती है तो अगला राजकोषीय वर्ष भी किसी तरह बेहतर नहीं हो पाएगा।

यदि सरकार अपने जीडीपी के 7. 6 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे को 5. 1 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती है तो यह सब कुछ दूर का सपना ही साबित होगा।

ljdkj dk Ñf"k {k= ij è;ku nsuk vko';d gS ijUrq ctV esa dkbZ dkjxj uhfrxr mik;, ugha fd, x, gSa vkSj u gh bl chekj {k= ds fy, vkoaVu fd;k x;k gSA ctV esa 5]75]000 djksM+ #i, ds Ñf"k _.k dk y{; c<+k;k x;k gS ijUrq vkdMk ls irk pyrk gS fd NksVs fdlku Ñf"k _.kksa ij vfèkd C;kt ds dkj.k cSad _.k ysus esa vleFkZ jgsaxsA foÙk ea=h dks lqfuf'pr djuk pkfg, Fkk fd og Ñf"k _.kksa ds izokg dks lgh ykxksa rd vkSj lgh fn'kk esa igqpk ikrhA

पूर्वी भारत के धान पैदा करने वाले क्षेत्रों में कृषि के लिए आबंटित धन की बढ़ी हुई व्यवस्था जिसे 400 करोड़ रूपए से बढ़ा कर 1000 करोड़ रूपए किया गया है, स्वागत–योग्य कदम है परन्तु बजट में इन क्षेत्रों में धान पैदा करने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। ये किसान गहन संकट हैं क्योंकि उन्हें अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। केन्द्रीय बजट में इन किसानों को बेहतर मूल्य देने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी।

सरकार ने 'सिंगल सुपर फॉसफेट' (एसएसपी) को प्रोत्सहित करने का वायदा किया है, परन्तु किसान समुदाय का मानना है कि एसएसपी से मिट्टी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बजट में मौसमी बदलाव के कारण विभिन्न बीज किस्मों के विकास के अनुसंधान के लिए 200 करोड़ रुपए का आबंटन किया है परन्तु इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस उपाए से भारतीय किसान आनुवंशिक संशोधित बीजों के जाल में नहीं फंस जाएंगे।

यदि वित्तमंत्री भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते तो इस वर्ष का बजट विकास की दिशा में बढ़ने का साधन हो सकता था। परन्तु बजट उस दिशा में बढ़ पाया है और यह यूपीए सरकार की आर्थिक मोर्चे पर अनिर्णय तथा भ्रम की स्थिति को ही दर्शाता है। ■

चुनौतियों का सतही जवाब

& ;'kor flUgk

वित्त मंत्री अनेक मोर्चों पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनका बहादुरी के साथ सामना करने के बजाय उन्होंने समर्पण कर दिया है, जिससे देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियां और गंभीर रूप धारण करेंगी। सबसे बड़ी चुनौती थी राजकोषीय और आय के घाटे को घटाते हुए बजट को संतुलित करना। वह इस मोर्चे पर बुरी तरह विफल रहे। आंकड़ों की बाजीगरी के बावजूद चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 फीसदी पर आ गया है।

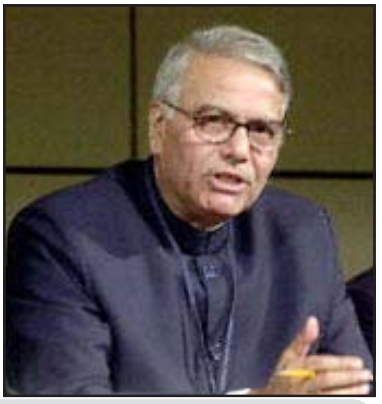

;ह संप्रग सरकार का नौवां बजट था और अगर वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए मनमोहन सिंह के पांच बजट भी इस सूची में जोड़ लिए जाएं तो यह उनका 14वां बजट था। देश की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ दोहरे अंकों में ले जाने के लिए किसी को कितना समय और कितने बजट चाहिए? एक बड़ा अवसर गंवा दिया गया। वित्त मंत्री अनेक मोर्चों पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनका बहादुरी के साथ सामना करने के बजाय उन्होंने समर्पण कर दिया है, जिससे देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियां और गंभीर रूप धारण करेंगी। सबसे बड़ी चुनौती थी राजकोषीय और आय के घाटे को घटाते हुए बजट को संतुलित करना। वह इस मोर्चे पर बुरी तरह विफल रहे। आंकड़ों की बाजीगरी के बावजूद चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 फीसदी पर आ गया है। मेरी अपेक्षा थी कि राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाने के लिए वित्त मंत्री अगले वर्ष खर्चों में कटौती करेंगे। वह ऐसा कर सकते थे। इसके लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली 200 योजनाओं के लाभार्थियों की सही पहचान के काम को अंजाम देकर योजनाओं के खर्च में कटौती करना था और सरकार के गैरजरूरी खर्चों में कमी लाने की जरूरत थी। वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, ने कुछ माह पहले ही भारत सरकार को योजनाओं की संख्या कम करने की अनुशंसा की थी। उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण सड़क, पीने का पानी और साफ–सफाई, कृषि, आवास, ऊर्जा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक ही इन योजनाओं को सीमित रखना चाहिए था। इसके पीछे तर्क यह था कि देश के अलग–अलग भागों की अलग–अलग आवश्यकताएं हैं। ऐसे में क्षेत्रीय आवश्यकताओं की बेहतर समझ रखने वाले राज्य ही उपयुक्त योजनाएं ला सकते हैं। दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी उन स्थानों के लिए सही योजनाएं तैयार नहीं कर सकते, जहां उनकी पहुंच ही नहीं है। मनरेगा, एनआरएचएम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और इस प्रकार की अन्य अनेक योजनाओं में भ्रष्टाचार जगजाहिर है। इन योजनाओं से लोगों को बहुत कम लाभ हुआ है। उदाहरण के लिए एक साल में औसत परिवार को महज 32 दिन ही काम मिला है। क्या 32 दिन कमाकर कोई 365 दिन जिंदा रह सकता है? देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। फिर भी वित्त मंत्री इस तूफान से पूरी तरह बेपरवाह नजर आते हैं। वह योजनाओं में कटौती करने के बजाय इन्हें बराबर बढ़ा रहे हैं। सख्त अर्थव्यवस्था और नियंत्रित खर्च के विचार का बजट में उल्लेख तक नहीं किया गया। अगले साल के लिए 5.1 फीसदी राजकोषीय घाटा सरासर अस्वीकार्य है। अर्थव्यवस्था पर इसके घातक असर का अनुमान लगाना आसान है। वर्तमान हालात में जब ऋण 513,590 करोड़ रुपये पर यानी भारत सरकार के कुल खर्च के एक–तिहाई स्तर पर पहुंच गया है, और ऋण लेने से महंगाई बढ़ेगी और निजी निवेश हतोत्साहित होगा। ऊंची मुद्रास्फीति से आरबीआई ब्याज की दरें कम नहीं कर पाएगा, जिससे निजी क्षेत्र के उत्पादक निवेश पर और मार पड़ेगी। यह खतरनाक चक्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और अगले वित्त वर्ष में 7.6 फीसदी विकास दर एक स्वप्न बन कर रह जाएगी। करों के मामले में वित्त मंत्री ने वह कर दिया

जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर आम आदमी पर 45940 करोड़ रुपये का बोझ डाल दिया है। करों में इस प्रकार की वृद्धि अभूतपूर्व है। यह वृद्धि तब की गई है जब रेलवे ने माल भाड़े और यात्री किराए में वृद्धि के रूप में आम आदमी पर पहले से बीस हजार करोड़ रुपये का बोझ डाल दिया है। मुझे आशा थी कि वित्त मंत्री प्रत्यक्ष कर संहिता के संदर्भ में संसद की स्थायी समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त मंत्री के टैक्स प्रस्तावों के संदर्भ में एक अन्य विचलित करने वाली बात उन वस्तुओं की सूची है जिनमें उन्होंने केंद्रीय एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, दोनों में कुछ राहत दी है। इससे कर से संबंधित दर्शन ही गड़बड़ा गया है। यह पहलू उस सफाई अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो मैंने अपने बजटों में अप्रत्यक्ष करों पर आरंभ किया था। मौजूदा वर्ष में सरकार का कुल खर्च 1,257,729 करोड़ रुपये था। बदले अनुमान के तहत यह बढ़कर 1,318,720 करोड़ रुपये हो गया। अगले वर्ष के लिए बजट खर्च 1,490,925 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। कुल बजट खर्च में भारी वृद्धि के बावजूद रक्षा बजट में बहुत मामूली वृद्धि की गई है। रक्षा बजट में यह बढ़ोतरी बस मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखकर ही की गई है। यह स्थिति तब है जब चीन और पाकिस्तान, दोनों ही देश अपने रक्षा बजट में भारी वृद्धि करते जा रहे हैं। इस लिहाज से हमारी रक्षा तैयारियां स्पष्ट रूप से कमजोर नजर आ रही हैं। सब्सिडी की ही तरह वित्त मंत्री को साल बीतने के साथ रक्षा खर्च में बढ़ोतरी करनी होगी और इससे हमारे राजकोषीय घाटे पर और अधिक दबाव पड़ना तय है। यह भी हैरत की बात है कि बजट आर्थिक सुधारों के संदर्भ में पूरी तरह खामोश है। विनिवेश, जिससे वित्त मंत्री को मौजूदा वित्तीय वर्ष में चालीस हजार करोड़ रुपये हासिल होने की आशा है, सरकार की असफलता का एक क्षेत्र नजर आ रहा है। इस बजट का सबसे खराब पहलू विश्वसनीयता का अभाव है। बजट अनुमान अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। यहां तक कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो घोषणाएं कीं वे टिकाऊ नजर नहीं आतीं और उनको लेकर कोई भरोसा उत्पन्न नहीं हो रहा है। यह तर्क कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो परेशानियां दिखाई दे रही हैं वे वैश्विक संकट की देन हैं। 2008–09 की तरह गत वर्ष भी सरकार वैर्श्विक संकट का अनुमान नहीं लगा सकी और इसका दोष उसके ही मत्थे आएगा। पिछले वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण उत्साह से भरे थे और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए नौ प्रतिशत की विकास दर की भविष्यवाणी की गई थी। वित्त मंत्री ने भी अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि 2010–2011 में हमारी विकास दर प्रवाहमय और व्यापक आधार वाली रही है। अब 12 महीने के भीतर ही यह स्पष्ट हो रहा है कि उनका यह दावा कितना खोखला था? इस बजट का राजनीतिक संदेश यही है कि चौतरफा घिरी सरकार में देश के सामने उभर रहीं समस्याओं का सामना करने का साहस नहीं है। देश को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से नेतृत्व की आशा थी, लेकिन वे इस अपेक्षा में खरे नहीं उतरे। ■

वर्तमान हालात में जब ऋण 513,590 करोड़ रुपये पर यानी भारत सरकार के कुल खर्च के एक–तिहाई स्तर पर पहुंच गया है, और ऋण लेने से महंगाई बढ़ेगी और निजी निवेश हतोत्साहित होगा।)ंची मु•ास्फीति से आरबीआई ब्याज की दरें कम नहीं कर पाएगा, जिससे निजी क्षेत्र के उत्पादक निवेश पर और मार पड़ेगी। यह खतरनाक चट्ट विकास पर नकारात्मक श्भाव डालेगा और अगले विट्ठा वर्ष में 7.6 फीसदी विकास दर एक स्वप्न बन कर रह जाएगी।

¼y[kd io foÙk e=h g½
¼nfud tkxj.k d lktU; l½

बजट सरकार का विदाई बिगुल : नकवी

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ''दीदी की बगावत के बीच दादा का बजट सरकार का विदाई बिगुल'' साबित होगा। श्री नकवी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि सरकार ने, नाकाम हो चुके अपने ''अर्थशास्त्र'' के फार्मूले को फिर से नए फ्रेम में फिट कर के पेश किया है, जो कि ना तो जन सरोकार में मददगार होगी ना ही चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था को ठीक कर पाएगा। यह बजट देश को ''उदारीकरण के बजाय उधारीकरण'' के रास्ते पर ले जाने वाला है। श्री नकवी ने कहा कि चौतरफा दबाव से जूझ रही सरकार ने आम आदमी, और गरीबों के कंधों पर आंकड़ों की बाजीगरी से बोझ का वजन बढ़ा दिया है। इस बजट के बाद जमीन से लेकर आसमान तक महंगाई आम आदमी के सर चढ़ कर बोलेगी। ■

चुनौतियों से मुंह मोड़ता बजट

& ,u d flg

एक पुरानी कहावत है कि बजट सभी आर्थिक समस्याओं का रामबाण इलाज नहीं होता। आर्थिक समस्याओं को आर्थिक नीतियों से सुलझाया जाता है और ये नीतियां पूरे साल बनती रहती हैं, जबकि बजट साल में सिर्फ एक बार आता है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में अगले वित्त वर्ष का जो बजट पेश किया है, उसमें ऐसी नीतियों का जिक्र तो है, जिनसे कई आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, लेकिन ये नीतियां बजट में कहीं लागू होती नहीं दिख रहीं। देश के सामने इस समय तीन बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और यह बजट इन तीनों ही चुनौतियों का ठीक से मुकाबला करता नहीं दिख रहा है।

पहली चुनौती विकास दर में आई गिरावट को लेकर है। जीडीपी की विकास दर 6.9 फीसदी तक पहुंच गई है। यह सबसे चिंताजनक पहलू है। आप उसे अगले वित्त वर्ष में बढ़ाकर 7.6 फीसदी तक ले जाना चाहते हैं, और उसके अगले वर्ष में इसे 8.6 फीसदी तक ले जाने का इरादा है। लेकिन विकास दर को किस तरह बढ़ाया जाएगा, बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर हम देखें, तो इस समय निवेशकों के हौसले पस्त हैं। अगर निवेश बढ़ेगा, तो जीडीपी भी बढ़ेगी। लेकिन बजट में ऐसी नीतियों का उल्लेख नहीं है, जो विकास दर बढ़ाने की उम्मीद बंधाती हों या निवेशकों को यह भरोसा देती हों कि उनका निवेश फलदायी होगा।

दूसरी बड़ी चुनौती वित्तीय घाटे को लेकर है। दरअसल इसके साथ ही चालू खाते का घाटा भी हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। इन दोनों को मिलाकर जुड़वां घाटा कहा जाता है, यह जुड़वां घाटा तेजी से बढ़ रहा है। वित्तीय घाटा 5.9 फीसदी तक चले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अंत में यह वित्तीय घाटा छह फीसदी तक पहुंच ही जाएगा। अब अगर इसमें राज्यों का भी वित्तीय घाटा जोड़ लिया जाए, तो यह नौ फीसदी तक हो जाएगा, जो काफी खतरनाक है। वित्तीय घाटा तब बढ़ता है, जब सरकार की आमदनी कम हो और खर्च बढ़ जाए। आर्थिक मंदी के कारण जीडीपी घटी है, तो सरकार का राजस्व भी घटना ही था। फिर सरकार ने विनिवेश का जो लक्ष्य तय किया था, वह भी पूरा नहीं हो सका। समस्या यह है कि आगे के लिए भी कोई बड़ी उम्मीद नहीं बंधती।

वित्त मंत्री ने यह जरूर कहा है कि वह वित्तीय घाटे को एक फीसदी तक घटाएंगे। लेकिन कैसे? यह तब तक संभव नहीं है, जब तक आप सब्सिडी को नहीं घटाते। ऑयल सब्सिडी के बारे में कहा गया है कि डीजल और केरोसिन की सब्सिडी अब सीधे उपभोक्ताओं को नकदी के रूप में सौंपी जाएगी। लेकिन यह डॉयरेक्ट कैश ट्रांस्फर होगा कैसे? जिन उपभोक्ताओं को इसका फायदा देना है, क्या उनकी पहचान कर ली गई है? नहीं, तो कब तक की जाएगी? कब तक कैश ट्रांस्फर का तंत्र बनकर पूरी तरह तैयार हो पाएगा? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन्हें इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा, उन्हें क्या बाजार दर पर डीजल और केरोसिन मिलेगा? अगर ऐसा है, तो यह बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव होगा।

लेकिन इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। कैश ट्रांस्फर की बात ही यूरिया पर सब्सिडी के मामले में की गई है। और वहां भी सवाल यही है। बजट में यह तो कहा गया है कि सब्सिडी को जीडीपी की दो फीसदी से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह एक वायदा, एक लक्ष्य भर है। जब तक आप इसका सही तरीका नहीं साफ करते, इस पर विश्वास कौन करेगा? बाजार को सहज ही यह विश्वास नहीं होगा कि इस लक्ष्य को हासिल भी किया जा सकता है या नहीं।

तीसरी चुनौती कुछ खास क्षेत्रों में संरचनात्मक बदलावों को लेकर थी। बजट में इसके लिए भी बहुत कुछ नहीं किया गया। हम विकास में मैन्यूफैक्चरिंग

> ***विद्रा मंत्री श्णब मुखर्जी ने संसद में अगले विद्रा वर्ष का जो बजट पेश किया है, उसमें ऐसी नीतियों का जिट्ट तो है, जिनसे कई आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, लेकिन ये नीतियां बजट में कहीं लागू होती नहीं दिख रहीं। देश के सामने इस समय तीन बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और यह बजट इन तीनों ही चुनौतियों का ठीक से मुकाबला करता नहीं दिख रहा है।***

क्षेत्र की बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार इसी क्षेत्र में मिल सकते हैं। इसी तरह विद्युत, नागरिक उड्डयन और गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलावों की जरूरत थी, लेकिन वैसा दिखा नहीं। विद्युत व नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए जो किया भी गया, वह बहुत कम है।

इन दोनों क्षेत्रों को एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग की इजाजत दी गई है, जिससे इस क्षेत्र की पूंजी की समस्या कुछ हद तक खत्म होगी। उड्डयन के लिए टरबाइन फ्यूल को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, हालांकि इस मामले में सेल्स टैक्स का मसला सुलझाने की जरूरत थी, जिसके लिए कुछ नहीं किया गया। विद्युत क्षेत्र के लिए इतना भर किया गया कि कोयला कंपनियों को अबाध आपूर्ति के लिए बाध्य किया जाएगा,

क्षेत्रीय विषमता व आमदनी की असमानता को कम करने के लिए कदम उठाने की जरूरत थी। दोनों तरह की विषमताएं हमारे देश में तेजी से बढ़ रही हैं। इसके लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

लेकिन कोयले के कारोबार में सुधार की जरूरत थी, उसके लिए कोई बात नहीं दिखी।

इन तीन चुनौतियों के अलावा क्षेत्रीय विषमता व आमदनी की असमानता को कम करने के लिए कदम उठाने की जरूरत थी। दोनों तरह की विषमताएं हमारे देश में तेजी से बढ़ रही हैं। इसके लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

बजट में कुछ अच्छी चीजें हैं। एक तो इसमें डॉयरेक्ट टैक्स कोड के लागू होने का इंतजार नहीं किया गया है। उससे जो सुविधाएं करदाताओं को मिलनी थीं, वे वैसे ही दे दी गई हैं। काले धन को कम करने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। जीएसटी की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। फिलहाल जो राजनीतिक हालात हैं,उनमें इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। वित्त मंत्री ने एक तरह की होल्डिंग एक्सरसाइज की है। दो दिन पहले रेल बजट के बाद जो राजनीति हुई, वे अपने बजट के लिए वैसा हश्र नहीं चाहते होंगे। इस लिहाज से यह राजनीतिक स्थिरता का बजट है। इसमें राजनीतिक स्थायित्व का लक्ष्य ज्यादा दिखाई देता है, आर्थिक स्थायित्व का कम। खामियों व चंद अच्छी चीजों के बाद भी यह एक औसत बजट ही है। ■

¼y[kd iwoZ dsUnzh; lfpo o jkT;lHkk lnL; gSa½ ¼fgUnqLrku½ ds lkStU; ls½

ढूंढे से भी बजट में आम आदमी नजर नहीं आता : नरेन्द्र मोदी

Xजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समूचे बजट में ढूंढने से भी 'आम आदमी' नजर नहीं आता। बजट जनविरोधी है। आर्थिक स्थिरता एवं विकास के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के बदले बजट में केन्द्र सरकार की राजनीतिक अस्थिरता का सीधा प्रभाव नजर आता है।

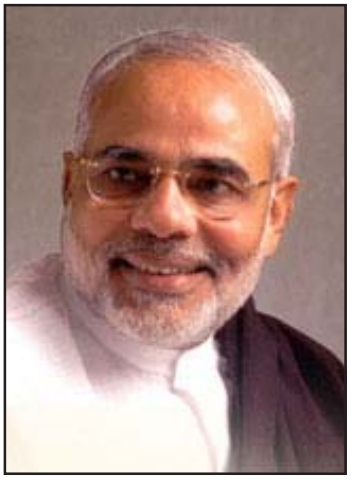

कमोबेश, बजट निस्तेज, देश की उम्मीदों के उलट एवं आर्थिक दुर्दशा की स्थिति को बद से बदतर होने का आभास करवाने वाला है। सामान्य लोगों पर 80 हजार करोड़ का नया बोझ (40 हजार करोड़ रेलवे के बजट सहित) लादा गया है। एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स में दो फीसदी की वृद्धि केन्द्र सरकार की 'आम आदमी' पर क्रूरता की तरह है। सर्विस टैक्स की मार पर्यटन उद्योग पर पड़ेगी, जिससे रोजगारपरक विकास प्रभावित होगा। वास्तविक विकास के बारे में दिशा शून्यता नजर आती है।

केन्द्र सरकार ने वित्तीय अव्यवस्था का दृष्टांत पेश किया है। बीते साल वित्तीय घाटा 4.6 आंका गया था, जो बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गया है। अगले साल यह 5.1 फीसदी रहेगा। केन्द्र सरकार की 'मार्केट बोरोइंग' 3.53 लाख करोड़ से बढ़कर 4.79 लाख करोड़ हो गया है। कृषि व महिला सशक्तिकरण क्षेत्र की अवहेलना की गई है। विकास खर्च केन्द्र का 30 प्रतिशत दर्शाया गया है।

गुजरात का विकास खर्च 67 प्रतिशत है। आदिवासी संबंधी उपयोजना के लिए बजट में 21000 करोड़ रुपए के आवंटन की बात कही गई है। गुजरात आदिवासियों पर पांच साल 40000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है।■

महंगाई बढ़ाने वाला बजट

& ykMZ es?kukFk nslkbZ

एक ऐसे समय जब गिरती विकास दर को तेज करने और बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए बजट से कुछ उम्मीदें की जा रही थीं तो वित्तमंत्री ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसमें अर्थव्यवस्था के बजाय सरकार की स्थिरता को अधिक महत्व दिया गया। संप्रग सरकार की कमजोर स्थिति को देखते हुए वैसे भी कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ तो किया ही जा सकता था। सरकार ने अगस्त, 2012 तक जीएसटी को लागू करने की बात कही है, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि इसे लागू करने से पहले राज्यों को होने वाले घाटे की क्षतिपूर्ति के संबंध में राज्य सरकारों से केंद्र को विचार–विमर्श करना होगा। सरकार ने डीटीसी यानी प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू करने की बात की है, जिसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही था किस तरह सरकार लगातार बढ़ रहे राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाएगी और सब्सिडी की समस्या से निपटेगी, लेकिन इन दोनों ही प्रश्नों का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। वित्तमंत्री की मानें तो आगामी वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1 प्रतिशत के स्तर पर आ जाएगा, जो फिलहाल 5.9 है। मेरे विचार में यह अतिरंजित विचार है, क्योंकि इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे और रोडमैप क्या होगा, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया।

कुछ ऐसा ही हाल आर्थिक विकास दर का भी है। वित्तमंत्री ने उम्मीद जताई है कि आगामी वित्तीय वर्ष में 7.6 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर ली जाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री ने 8.5 प्रतिशत विकास दर हासिल करने की बात कही थी, लेकिन आज हमारी विकास दर 6.9 है। कुछ ऐसा ही हाल महंगाई के आंकड़ों का है। इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के विकास के लिए बजट में तकरीबन 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने थोड़ा–बहुत ध्यान अवश्य दिया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं। रोजगार बढ़ाने के उपायों की चर्चा वित्तमंत्री ने नहीं की। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिन कदमों को उठाए जाने की आवश्यकता थी वैसा कुछ नहीं किया गया। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने विदेशी कंपनियों को छूट देने की बात कही है, लेकिन हम जानते हैं कि विदेशी निवेश अपनी शर्तों पर आता है और जब हमारा बाजार अच्छा होगा, इसमें सुधार होगा तभी विदेशी निवेशक यहां आने के लिए सोचेंगे। इसलिए सरकार जब तक समग्रता में कदम नहीं उठाती है तब तक इस तरह के प्रयास अच्छे परिणाम शायद ही दे सकें। बजट में खुदरा क्षेत्र में एफडीआइ के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की गई है। ऐसा शायद इसलिए है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि उसके सहयोगी दल इसके लिए शायद ही तैयार हों।

इस बजट में आम आदमी के लिए भी कुछ खास नहीं है। आयकर की सीमा को एक लाख 80 हजार से बढ़ाकर दो लाख कर दिया गया है। यह वृद्धि 20 हजार की है, जिससे लोगों को तकरीबन दो हजार रुपये टैक्स की बचत होगी, लेकिन सेवा कर और उत्पाद कर में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस तरह महंगाई में जो बढ़ोतरी होगी उसकी तुलना में यह छूट कुछ खास नहीं कही जा सकती। इस कदम से आम उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा होगा और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव औद्योगिक विकास पर पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी। मेरे विचार से यह एक विरोधाभासी कदम है, जिसका कोई औचित्य नहीं था। इसके अतिरिक्त एक

> ***फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही था किस तरह सरकार लगातार बढ़ रहे राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाएगी और सब्सिडी की समस्या से निपटेगी, लेकिन इन दोनों ही श्नों का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। विद्गामंत्री की मानें तो आगामी विद्गीय वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1 श्तिशत के स्तर पर आ जाएगा, जो फिलहाल 5.9 है। मेरे विचार में यह अतिरंजित विचार है, क्योंकि इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे और रोडमैप क्या होगा, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया।***

विरोधाभास यह भी है कि जहां एक तरफ सरकार सब्सिडी को अगले तीन सालों में घटाकर कुल जीडीपी के 1.7 प्रतिशत पर लाने की बात कह रही है, वहीं वह खाद्य सुरक्षा बिल को अमलीजामा पहनाने की बात भी कह रही है। यदि इन सभी योजनाओं को लागू कर दिया जाता है तो सब्सिडी का हिस्सा बढ़कर दो लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगा। फिर किस तरह सरकार सब्सिडी पर नियंत्रण लगा सकेगी, जबकि उसकी नीतियां गैर–उत्पादक चीजों पर खर्च बढ़ाने की हैं। सब्सिडी के लिए सरकार नई सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को अपनाने की बात कह रही है और खाद्यान्नों व उर्वरकों पर सब्सिडी सीधे दुकानकारों को देने की वकालत कर रही है। मेरे विचार में यह सब ठीक नहीं। इससे कहीं अधिक अच्छा होगा कि लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए। राजीव गांधी इक्विटी योजना में पचास प्रतिशत टैक्स छूट की योजना एक अच्छा कदम है। इससे छोटे निवेशक भी बाजार में पैसा लगाएंगे, लेकिन इसके साथ–साथ सरकार को बचत बढ़ाने के बारे में कुछ उपाय करने चाहिए थे।

इस बजट में एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने काले धन पर संसद में श्वेत पत्र लाने का वायदा किया है और ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाने की भी बात कही है, लेकिन यह तभी कारगर होगा जब देश के भीतर भ्रष्टाचार की समस्या पर भी सरकार ध्यान दे और कठोर कानून बनाए। इस बजट में कारपोरेट जगत पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है और न ही कोई बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो यह एक निराशाजनक बजट है, जिसमें न तो आम लोगों के लिए कुछ खास है और न ही कारपोरेट जगत के लिए। इसके लिए सरकार तर्क दे रही है कि ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्थितियों खासकर यूरोजोन संकट के कारण है, लेकिन मेरे विचार में यह सही नहीं। असली संकट तो तब आएगा, यदि इजरायल और पश्चिमी देश ईरान पर हमला कर देते हैं, क्योंकि इससे तेल की कीमतें आसमान छूने की आशंका है। यदि ऐसा हुआ तो राजकोषीय घाटे का आंकड़ा और बड़ा हो जाएगा, जिसमें महंगाई आग में घी का काम करेगी। यह बजट न तो दूरदर्शी है और न ही प्रगतिशील। ■

¼ys[kd ç[;kr vFkZ'kkL=h gSa½
¼nSfud tkxj.k ds lkStU; ls½

उद्योग जगत ने कहा, बजट महंगाई बढ़ाने वाला

mद्योग जगत ने वित्त वर्ष 2012–13 के बजट को निराशाजनक करार देते हुए कहा है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और उपभोक्ता मांग प्रभावित होगी। उद्योग जगत ने कहा है कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट में अधिक कर जुटाने का प्रयास किया है और एक अवसर गवां दिया है।

फिक्की के अध्यक्ष आर वी कनोड़िया ने कहा कि इस बजट से अर्थव्यवस्था की रतार नहीं बढ़ने वाली। वहीं सीआईआई के अध्यक्ष बी मुत्तुरमन ने कहा कि वह और अधिक की उम्मीद कर रहे थे और उत्पाद शुल्क आधारित प्रस्तावों से दाम और चढ़ेंगे। मुत्तुरमन ने कहा कि राजकोषीय घाटे को कम करने के कदम से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।

सी के बिड़ला समूह के सिद्धार्थ बिड़ला ने कहा कि इस बजट ने मौका गंवा दिया। बायोकान की चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ ने आशंका जताई कि बजट मुद्रास्फीतिक दबाव बढ़ाने वाला साबित होगा।

जे के समूह के हर्षपति सिंघानिया ने इसी तरह की राय जाहिर करते हुए कहा कि उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ेगी। नकदी की कमी से जूझ रही सरकार ने 2012–13 में 45,940 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर जुटाने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव ऐसे समय किया गया है जब उद्योग जगत पहले से मांग की कमी से जूझ रहा है।

गोदरेज समूह के चेयरमैन आदि गोदरेज ने कहा कि घाटा अभी भी काफी ऊंचा है जो निराशाजनक है। अंतिम उपभोक्ता के लिए चीजें महंगी होंगी।

एसोचैम के अध्यक्ष आर एन धूत ने कहा कि वह आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये किए जाने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा नहीं हुआ, जो निराशाजनक है।

कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने बजट की कड़ी आलोचना करते हुए इसे महंगाई बढ़ाने वाला दस्तावेज बताया है जो आम आदमी की कमर तोड़ देगा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने संयुक्त बयान में कहा कि सेवा कर और उत्पाद शुल्क को 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किए जाने से हर चीज महंगी हो जाएगी। उत्पाद और सीमा शुल्क में बढ़ोतरी का मुद्रास्फीतिक असर पड़ेगा।

कोटक महिंद्रा समूह के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक उदय कोटक ने कहा कि मुझे लगता है कि देर–सवेर सरकार डीजल के दाम बढ़ाएगी। ■